दैनिक
उजाला संदेश
राष्ट्रधर्म सर्वोपरि

RNI No. MPHIN/2022/83759

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र | भोपाल, मंगलवार 14 अप्रैल, 2026 | वर्ष-04 अंक-131 पेज-08 मूल्य-1.00/-

सुविचार

अगर आप स्वयं पर विश्वास कर सकते हैं, तो अन्य भी आप पर विश्वास कर सकेंगे।

संक्षिप्त समाचार

आज जारी होगा एमपी बोर्ड रिजल्ट

- टॉपर्स को कैश प्राइज और लैपटॉप देगी सरकार

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से भोपाल स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। रिजल्ट की ऑफिशियल डेट MPBSE ने सोमवार को ही जारी कर दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी रिजल्ट की तारीख की पुष्टि कर दी थी। इस साल एमपी बोर्ड परीक्षा में

शामिल होने वाले स्टूडेंट रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के टॉपर्स का नाम भी जारी किया जाएगा और फिर उसके बाद जो टॉपर्स होंगे उन्हें राज्य सरकार की ओर से कैश प्राइज और अन्य ईनाम के साथ सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य में टॉप पोजिशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सम्मानित किया जा सकता है। साथ ही प्राइज मनी और ईनाम भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को सरकार की ओर से 25 हजार रुपए की कैश राशि और लैपटॉप दिया जाएगा। मुख्य पुरस्कारों में मेधावी छात्राओं को स्कूटी और ग्रामीण क्षेत्रों के टॉपर्स को साइकिल दी जा सकती है। 12वीं के जिन स्टूडेंट्स ने 75 परसेंट या उससे ज्यादा नंबर मिलेंगे उन्हें कैश प्राइज मिलेगा। पिछले साल टॉपर्स को यही सब दिया गया था। 2025 में एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने टॉप किया था।

जनगणना में गलत जानकारी देने पर 3 साल की जेल

- महिलाओं से जबरन नाम नहीं पूछ सकेंगे सरकारी कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में जनगणना के लिए काउंट डाउन शुरू होने वाला है। रक्षागृह विभाग को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा। गृह विभाग ने जनगणना कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गाइडलाइन के मुताबिक, एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर को अगर कोई भी व्यक्ति जनगणना के लिए गलत जानकारी देता है, तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर परिवार की किसी महिला का नाम बताने से इनकार करता है तो जनगणनाकर्मी जबरदस्ती नाम नहीं पूछ सकेंगे।

सवालों के जवाब देना नागरिकों की जिम्मेदारी- गृह विभाग ने कहा कि जनगणना के लिए अधिकृत अधिकारी केंद्र सरकार से तय किए गए सभी सवाल पूछ सकते हैं। हर नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह इन सवालों का जवाब दे। यानी सामान्य जानकारी देने से कोई इनकार नहीं कर सकता।

जनगणना अधिकारियों को प्रवेश से नहीं रोक सकेंगे- नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जनगणना अधिकारियों को अपने घर, अहाते, जलयान या अन्य स्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोक सकेगा। बशर्ते वह स्थान परंपरागत रूप से प्रतिबंधित न हो। साथ ही अधिकारियों को जरूरी आंकड़े दर्ज करने से भी नहीं रोका जा सकेगा। गृह विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

दिल्ली से देहरादून का सफर अब मात्र ढाई घंटे में

- पीएम मोदी ने किया दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
- मोदी ने कहा-2029 के चुनावों में बेटियों को उनका हक देंगे

देहरादून (एजेंसी)। पीएम मोदी ने मंगलवार को देहरादून में कहा, '4 दशकों से महिला-बेटियां अपने हक का इंतजार कर रही है। अब वह समय आ गया है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे। इसके लिए हम संसद में महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं।' पीएम ने कहा, कभी उत्तराखंड के गांव में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थीं। आज डबल इंजन सरकार के प्रयास से सड़क गांव तक पहुंच रही है। जो गांव वीरान थे आज फिर बस रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वे एशिया के सबसे लंबे 12 किमी एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण करने सराहनपुर पहुंचे। यहां रोड शो भी किया। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 213 किमी लंबा, 6 लेन और एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है।

महिला आरक्षण पर पीएम ने रखी अपनी बात

4 दशक बाद संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। 33% आरक्षण लागू करने वाले इस कानून को बनाने के लिए सभी दलों ने समर्थन दिया। अब इसे लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। 2029 से ही यह लागू हो जाना चाहिए। यह देश की भावना है हर बहन बेटी की इच्छा है।मातृशक्ति की इसी इच्छा को नमन करते हुए 16 अप्रैल से संसद में चर्चा होनी है। इसे सभी दल सर्व सम्मति से आगे बढ़ाएं। इसलिए मैंने आज देश की नारी शक्ति के नाम आज सभी बहनों के लिए एक पत्र लिखा है। हम अपने देश की बेटियों को 2029 के चुनावों में उनका हक देकर रहेंगे।

देवभूमि को गंदगी से बचाना जरूरी

पीएम ने देवभूमि को साफ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक और कचरे से बचना जरूरी है। कुंभ और नंदा देवी राजजात यात्रा को देखते हुए सभी को मिलकर इन जगहों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना होगा। पीएम ने कहा कि सड़क, रेल और एयरवे देश की भाग्य रेखाएं हैं। यह सिर्फ आज की सुविधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है ताकि देश की प्रगति जारी रहे। पीएम सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचे और यहां से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर गए। वहां उन्होंने रोड शो किया।

टूरिज्म बना कमाई का सबसे बड़ा जरिया

पीएम ने कहा कि टूरिज्म बढ़ने से हर वर्ग को कमाई का मौका मिलता है। होटल, टैक्सी, दुकानदार सभी को लाभ होता है। उत्तराखंड अब

विंटर टूरिज्म और स्पोर्ट्स का बड़ा केंद्र बन रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। पीएम ने कहा कि एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर विकास के गेटवे हैं। इससे समय और खर्च दोनों कम होंगे।

बिहार को मिल गया नया 'सम्राट'

- भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का ऐलान, नीतिश की जगह लेंगे

आज होगी ताजपोशी, विधायक दल की बैठक में बने नेता

पटना (एजेंसी)। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। पटना में मंगलवार को हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में यह ऐलान किया गया। लगभग दो दशक तक बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सम्राट उनकी जगह लेंगे। बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बनेगा। नीतीश के डिप्टी रहे सम्राट चौधरी अब बिहार में एनडीए सरकार की कमान संभालेंगे। उनके नाम की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। नई सरकार का शपथ ग्रहण बुधवार को होगा। लोकभवन में सम्राट चौधरी को

राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ कुछ और नेता भी शपथ ले सकते हैं।

विजय सिन्हा ने रखा सम्राट के नाम का प्रस्ताव

बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी गई। इसके बाद शिवराज नए सीएम का नाम लेकर पटना पहुंचे। पटना में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी विधायकों ने सहमति दे दी।

तीसरी बार चुने गए भाजपा विधायक दल के नेता

बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे सम्राट चौधरी लगतार तीसरी बाहर भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए। 2024 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ एनडीए में लौटे थे, तब सरकार गठन से पहले सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। उस समय वे पहली बार नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम बने थे। फिर नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए की सरकार बनी, तब भी सम्राट को ही भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। अब नीतीश के इस्तीफे के बाद नई सरकार के गठन से पहले भी उन्हें लगातार तीसरी बार नेता चुना गया है। नई सरकार के गठन को लेकर मंगलवार को पूरे दिन पटना में हलचल रही।

'सबका किनारा', होर्मुज स्ट्रेट में अकेला पड़ा अमेरिका

- यूके से लेकर जापान तक सबने ने एक साथ खींच लिए हाथ

तेल का दाम बढ़ाकर सहयोगियों को सजा देना चाहते हैं ट्रंप

वॉशिंगटन/तेहरान (एजेंसी)। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम का मकसद ईरानी जहाजों की आवाजाही रोकना है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो जहाज जो ईरान को टोल चुका रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए चाहे वो किसी भी देश के हैं। चीन जा रहे एक जहाज ने ट्रंप की चेतावनी को ताक पर रखते हुए होर्मुज पार कर लिया है और हमारी जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उसे नहीं रोका है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज खुलवाने के लिए दुनिया के देश आएं और ईरान से झगड़ा करें।

होर्मुज की घेराबंदी समझ से परे

हॉर्मुज स्ट्रेट एक संकरा समुद्री मार्ग है जिसका एक हिस्सा सिर्फ करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया के कुल तेल व्यापार का 20 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते से होता था। खाड़ी देश जैसे सऊदी, यूएई, कतर और खुद ईरान भी इसी रास्ते से अपने एनर्जी का निर्यात करते हैं। भारत, चीन समेत एशिया के करीब करीब सभी देश इस समुद्री रास्ते पर ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्भर हैं।

सीएम बोले-नारी सशक्तिकरण के साहसी और प्रबल समर्थक थे बाबा साहेब

संविधान निर्माता के साथ नए भारत के निर्माता भी हैं बाबा साहेब

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मभूमि पर उनकी जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहेब एक ऐसे युग दृष्टा थे, जिन्होंने एक हजार साल की गुलामी की कठिनाइयों को दूर करने और समाज के अंदर समानता के भाव को विकसित करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहेब के योगदान से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हमें उनके बनाए संविधान के अनुसार ही

- कहा-डॉ. अम्बेडकर ने संविधान के रूप में हमें दिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ

चलना चाहिए। इससे श्रेष्ठ संविधान और कोई नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. अम्बेडकर द्वारा महिला समानता और सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयासों और उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने बहनों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिलाने, तलाक के समय मुआवजा और मातृत्व अवकाश दिलाने के लिए सराहनीय कार्य किया।

लोकसभा और विधानसभा में सुनिश्चित होगा 33 प्रतिशत आरक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा साहेब महिला सशक्तिकरण के साहसी और प्रबल समर्थक थे। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने अपनी कुर्सी तक छोड़ दी थी। न्यूनतम मजदूरी, कंपनी लॉ और महिला श्रमिकों को अधिकार हमें बाबा साहेब की ही देन है। केन्द्र सरकार संविधान निर्माता डॉ. अम्बेडकर के आदर्शों पर चलते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आने वाले दिनों में लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू करने पर चर्चा होगी, इससे माताओं-बहनों को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा।

भीम जन्मभूमि पर आज होली-दीवाली जैसा माहौल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भीम जन्मभूमि पर आज होली-दीवाली जैसा माहौल है। बाबा साहेब के जीवन से जुड़े सभी 5 पड़ावों को हमारी सरकार ने पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया है। जातिगत असमानता को खत्म करने के लिए अंतर्जातीय विवाह करने पर नवदम्पतियों को हमारी सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपए दे रही है। अनुसूचित जाति-जनजाति के कल्याण के लिए सरकार ने सालाना बजट का एक तिहाई हिस्सा इन्हें समर्पित किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अनिल गजभिये और डॉ. सत्यभान मेश्राम द्वारा डॉ. अम्बेडकर के जीवन पर लिखी पुस्तक बाबा साहेब की दृष्टि में सामाजिक न्याय का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने डॉ. सुदीप भगतदीप, डॉ. संदेश माधवराव, स्व. श्री निशांत कायरे, डॉ. मीना गजभिये सहित 5 समाजेसवियों को भीमरत्न अवॉर्ड 2026 से सम्मानित किया।

दूसरे दिन भी बवाल

नोएडा में थमा नहीं टकराव

- 15 कंपनियों की फोर्स, 26 पुलिस अफसर भेजे

राहुल गांधी बोले- यह श्रमिकों की आखिरी चीख

गौतमबुद्धनगर (एजेंसी)। नोएडा, यानी गौतमबुद्ध नगर में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारी मंगलवार को भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2-3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया। प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। फिलहाल, पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवान इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। CCTV और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, पीएसी और RAF की 15 कंपनियां, 26 अफसर (8 एडिशनल एसपी और 18 डीएसपी) नोएडा भेजे गए हैं।

- यूपी सरकार ने देर रात फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई - इधर, यूपी सरकार ने सोमवार देर रात फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी। न्यूनतम मजदूरी दरों में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू होगी। सोमवार को बवाल के बाद हाईलेवल कमेटी ने रात में कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसके बाद रात डेढ़ बजे सरकार ने आदेश जारी कर कमेटी की सिफारिशों पर मुहर लगा दी।

राहुल बोले-

हर आवाज को अनसुना किया गया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ङ्क पर लिखा- कल नोएडा की सड़कों पर जो हुआ, वो देश के श्रमिकों की आखिरी चीख थी, जिसकी हर आवाज को अनसुना किया गया, जो मांगते-मांगते थक गया। कल 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की थी इससे पहले, नोएडा में सोमवार को अलग-अलग इलाकों में फैक्ट्री कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया। 9 अप्रैल से सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे 42 हजार कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की। 50 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दीं। 150 वाहन तोड़ दिए।

बंगाल में बोले राहुल गांधी, अमेरिका से ट्रेड डील को बताया धोखा

पीएम मोदी देशभक्त नहीं हैं बल्कि वह देशद्रोही हैं

कोलकाता (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला और उन्हें देशद्रोही तक बता डाला। राहुल गांधी ने कहा कि मालदा की रैली में कहा कि पीएम मोदी देश भक्त नहीं हैं बल्कि वह देशद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील देश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसके चलते देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का संकट भी पैदा होगा। उन्होंने इस दौरान स्ट्रक्की भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि स्ट्रक्में बड़ी संख्या में लोगों

के नाम हटाए गए हैं और ऐसा करना असंवैधानिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटे हैं। उन्हें कांग्रेस की सरकार आने पर वापस जोड़ा जाएगा।

नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है

राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4 हजार किलोमीटर चला। मेरा इरादा यही था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत से देश कमजोर होता है, जैसे परिवार में यह फैल जाती है तो फैमिली खत्म हो जाती है। ऐसी स्थिति देश की होती है। यदि आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखेंगे तो वह आंख में आंख में नहीं मिला पाते। मैं उनकी आंख में देखता हूं, लेकिन वह नीचे देखते हैं। वह कहते हैं कि हमारी 56 इंच की छाती है, लेकिन यह मजाक है। नरेंद्र मोदी ने तो देश को ही बेच दिया।

ट्रंप से यस सर-यस सर करते हैं पीएम मोदी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का पूरा कंट्रोल तो ट्रंप के पास है। ट्रंप यदि कहे कि आप जंप करिए तो कूदेंगे। वह कहे कि मेरे आगे झुक जाओ तो ये झुक जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कृषि सेक्टर अमेरिका के लिए खोल दिया है। इन लोगों ने अमेरिका के साथ ही तेल खरीदने का करार कर लिया है। उनसे कह दिया है कि यदि हम किसी और देश से तेल खरीदेंगे तो आपसे पहले पूछ लेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप से तो नरेंद्र मोदी बस 'यस सर, यस सर' करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों का पूरा डेटा ही नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को दे दिया है। इन्होंने ट्रंप से दावा किया है कि हर साल 9 लाख करोड़ का माल भारत अमेरिका से खरीदेगा।

छतरपुर में केन-बेतवा परियोजना को लेकर टकराव तेज!

एक ओर 'मिट्टी सत्याग्रह, दूसरी ओर सहमति से मकान हटाने की कार्रवाई

विस्थापितों का उग्र विरोध- भूख हड़ताल, नदी में उतरकर प्रदर्शन; प्रशासन का दावा- संवाद और सहमति से चरणबद्ध पुनर्वास प्रक्रिया जारी

स्पेशल स्टोरी

भोपाल/छतरपुर। हमारी जमीन छीन ली जा रही है, मगर बदले में न तो उचित मुआवजा तय है और न ही पुनर्वास का कोई ठिकाना तय हुआ है। 'हम जाएं तो जाएं कहां...?' यह सवाल पूछते हुए मनहारी गांव की कल्लों बाई की आवाज भर्रा जाती है। वह कहती हैं कि अब उनके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वे यहीं बैठकर अपने हक और अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगी। उनकी यह पीड़ा सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उन तमाम विस्थापित परिवारों की कहानी है जो अपनी जमीन और पहचान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल्लों बाई की आंखों में थकान है, लेकिन आवाज में अब भी जिद बाकी है। वह पिछले 9 दिनों से आंदोलन स्थल पर सैकड़ों आदिवासी किसानों के साथ डटी हुई हैं।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर संघर्ष अब खुलकर सामने आ गया है। एक ओर जहां हजारों आदिवासी, महिलाएं और बच्चे विस्थापन के विरोध में आंदोलन को तेज करते हुए 'मिट्टी सत्याग्रह' और भूख हड़ताल जैसे कदम उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन परियोजना के तहत जमीन खाली कराने की प्रक्रिया को सहमति और मुआवजे के आधार पर आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है। इन दोनों तस्वीरों ने पूरे मामले को संवेदनशील और जटिल बना दिया है।

द मूकनायक के प्रतिनिधि ने मौके पर पहुंचकर देखा कि आंदोलन अब एक बड़े जनसैलाब में बदल चुका है। छतरपुर मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर विजावर तहसील अंतर्गत केन नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में आदिवासी, महिलाएं और बच्चे चिचलाती धूप में खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। कई लोग शरीर पर मिट्टी लपेटे 'मिट्टी सत्याग्रह' कर रहे हैं, तो कुछ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इससे पहले आंदोलनकारियों ने अर्थी पर लेटकर भी अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसने पूरे माहौल को और अधिक भावुक बना दिया।

जल, जंगल, जमीन के नारे गूंजे- नदी किनारे 'जल, जंगल, जमीन' के नारे गूंज रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी हैं, वहीं बुजुर्ग अपनी जमीन और पहचान बचाने की बात करते हुए भावुक हो उठते हैं। वहां मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर थकान के साथ एक दृढ़ संकल्प भी दिखाई देता है, अपने हक और अस्तित्व की इस लड़ाई को किसी भी कीमत पर जारी रखने का। आंदोलन के नौवें दिन स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है, जब सोमवार सुबह बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी केन नदी में उतर गए। उन्होंने अपने शरीर पर गीली मिट्टी लपेटकर 'मिट्टी सत्याग्रह' शुरू किया और 'जल, जंगल, जमीन' के नारे लगाते हुए अपने अधिकारों की आवाज बुलंद की। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे इस भूमि के मूल निवासी हैं और बिना उचित मुआवजा व पुनर्वास के किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। कई बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि यदि उन्हें जबरन हटाया गया तो वे इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे।

आदिवासी किसानों का आकाश सत्याग्रह जारी- आंदोलन के दौरान विरोध के अनोखे और मार्मिक तरीके भी सामने आए हैं। 'मिट्टी सत्याग्रह' के तहत आंदोलनकारियों ने अपने शरीर पर मिट्टी मलकर यह संदेश दिया कि वे इसी जमीन के मूल मालिक हैं और इससे उनका गहरा संबंध है। कई बुजुर्गों ने भावुक होकर कहा कि यदि उन्हें बिना न्याय के उनकी जमीन से बेदखल किया गया, तो वे इसी मिट्टी में दफन होना पसंद करेंगे। वहीं 'आकाश सत्याग्रह' के तहत तपती धूप और खुले आसमान के नीचे हजारों विस्थापित बिना अन्न ग्रहण किए जमीन पर लेटकर विरोध जता रहे हैं। भूख और भीषण गर्मी के कारण कई महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है, जिससे आंदोलन की स्थिति और चिंताजनक हो गई है।

प्रदर्शन का स्वरूप केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक पीड़ा से भी भरा हुआ है। भीषण गर्मी के बीच खुले आसमान के नीचे 'आकाश सत्याग्रह' जारी है, जहां हजारों लोग जमीन पर लेटकर बिना अन्न ग्रहण किए विरोध कर रहे हैं। सामूहिक भूख हड़ताल के 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, जिसके कारण कई महिलाओं और बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ने लगी है।

मौके पर पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने स्थिति को और चिंताजनक बना दिया है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन उनकी हालत को नजरअंदाज कर रहा है और अब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है।

जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से कई परिवारों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, बावजूद इसके प्रशासन ने कोई ठोस पहल नहीं की है। उनका कहना है कि विस्थापन की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों, जैसे धारा 11, 15 और 18 की अनदेखी की जा रही है और लोगों को जबरन हटाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र होगा।

जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर ने द मूकनायक से बातचीत में प्रशासन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के 9वें दिन भी प्रशासन की चुप्पी यह साबित करती है कि गरीब आदिवासियों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों से आंदोलनकारियों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा है।

क्या है केन-बेतवा लिंक परियोजना?- केन-बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो योजना (River Linking Project) के तहत तैयार की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना है। इस परियोजना का मकसद बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करना, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना और पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके तहत केन नदी पर एक बड़ा बांध (दौधन बांध) बनाया जा रहा है, जिससे पानी को नहरों के जरिए बेतवा बेसिन तक ले जाया जाएगा। इससे लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और लाखों लोगों को पेयजल मिलने का दावा किया जाता है।

इस परियोजना की परिकल्पना कई दशक पहले की गई थी, लेकिन इसे वास्तविक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम साल 2021 में उठा, जब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच समझौता (स्थ्) हुआ। इसके बाद परियोजना को औपचारिक मंजूरी मिली और काम शुरू किया गया। हालांकि, जहां एक ओर इसे विकास और जल संकट के समाधान के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र और गांवों के डूब में आने तथा हजारों लोगों के विस्थापन को लेकर लगातार विरोध भी सामने आ रहा है।

प्रशासन ने 14 मकानों को हटाया

इसी बीच, प्रशासन ने जिले के विस्थापित ग्राम डुगरिया में जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, यहां 14 मकानों को हटाया गया है, प्रशासन ने दावा किया है, यह पूरी प्रक्रिया ग्रामीणों की सहमति और मुआवजा प्राप्त करने के बाद ही की गई। प्रशासन का कहना है कि 5 ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर अपने मकान हटाने के लिए बुलडोजर की मांग की, जिसे उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 9 ऐसे मकान हटाए गए जिनके मालिक पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे या जिनके पास गांव में एक से अधिक घर थे। प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि कार्रवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिन परिवारों के पास केवल एक ही घर है या जिन्होंने अभी तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है, उनके मकानों को नहीं छुआ गया। साथ ही जिन घरों में शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, उन्हें भी फिलहाल मोहलत दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाई जा रही है।

छतरपुर के स्थानीय पत्रकार संतोष सेन ने द मूकनायक से बातचीत में बताया कि केन-बेतवा परियोजना के विरोध में चल रहा आंदोलन अब धीरे-धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सैकड़ों लोग नदी के किनारे बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। संतोष सेन के मुताबिक, यह आंदोलन सिर्फ विस्थापन का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि आदिवासी समुदाय अपने 'जल, जंगल, जमीन' के संरक्षण और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है। लोगों में अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही है, जो इस आंदोलन को और व्यापक बना रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना को देश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में गिना जाता है, जिसका उद्देश्य जल संसाधनों का बेहतर उपयोग और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत देना है। लेकिन इस परियोजना की जमीनी हकीकत यह भी दिखा रही है कि विकास और विस्थापन के बीच संतुलन बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है। जहां एक तरफ प्रशासन चरणबद्ध तरीके से पुनर्वास और मुआवजे की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रभावित समुदाय अपने अस्तित्व और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल केन नदी के किनारे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ आंदोलनकारियों का आक्रोश और उनकी बिगड़ती सेहत है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्रवाई और परियोजना को आगे बढ़ाने का दबाव।

शोभायात्रा रूट पर चूने की जगह डाला कीटनाशक पाउडर, लोगों की सांसें हुईं परेशान

मंडीदीप। नगर पालिका मंडीदीप में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि स्वच्छता अधिकारी जावेद खान के निर्देश पर नगर में निकलने वाली शोभायात्रा के रूट मैप को चिन्हित करने के लिए चूने की जगह कीटनाशक पाउडर का छिड़काव कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि शोभायात्रा मार्ग पर दुकानों के सामने और मुख्य रास्तों पर डाले गए इस कीटनाशक पाउडर के कारण स्थानीय लोगों और दुकानदारों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने आंखों में जलन और घुटन जैसी शिकायतें भी जताई हैं। व्यापारियों का कहना है कि जहां चूने का उपयोग किया जाना चाहिए था, वहां जहरीले कीटनाशक का उपयोग करना गंभीर लापरवाही है, जो आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल इस पाउडर को हटाने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी स्वर भी तेज हो गए हैं। लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि 'मि. बंटाधार के नेतृत्व में सब कुछ संभव है। '

अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और आमजन को राहत दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है।

बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, गांव चलो अभियान में उमड़ा जनसैलाब

चिरापाटला मंडल में हेमंत खंडेलवाल का भव्य स्वागत, महिलाओं और नए मतदाताओं से किया संवाद

बैतूल। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत सोमवार को चिरापाटला मंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल का दौरा उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि वे बैलगाड़ी पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जिससे आयोजन आकर्षण का केंद्र बन गया। उनके आगमन पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय एवं भव्य स्वागत किया, जिससे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल नजर आया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री खंडेलवाल ने संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान के माध्यम से पार्टी सीधे जनता से संवाद स्थापित कर रही है। इस दौरान उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा कर

उनकी गतिविधियों की जानकारी ली और नवीन मतदाताओं का सम्मान करते हुए उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

चिरापाटला मंडल अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर घोड़ाडोंगरी विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके, भैंसदेही विधायक महेंद्र सिंह चौहान, जिला महामंत्री कृष्णा गायकी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष संतोष तेकाम, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिंह कुशवाह, पूर्व जनपद अध्यक्ष चिरोंजी लाला कवड़े, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष शंकर राव चढ़ोकार, पार्षद बाली आशुतोष मालवीय, संजय आवलेकर, मंडल महामंत्री आश्विन राठौर, रामपाल भलावी सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मांडवी आंगनवाड़ी में पोषण पखवाड़ा आयोजित

डॉ. अतुल राय ने दी पोषण, स्वच्छता व गर्भसंस्कार की जानकारी

बैतूल। ग्राम मांडवी के आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 3 में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शासकीय आयुर्वेद औषधालय मांडवी के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल राय द्वारा किया गया। यह आयोजन आयुक्त संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देश एवं कलेक्टर के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम पंचायत मांडवी की पंच सोनम झपाटे ने किया। इस अवसर

पर महिला एवं बाल विकास विभाग आठनेर की परियोजना अधिकारी रंजीता जोशी, पर्यवेक्षक हीरा बारपेटे सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं हितग्राही महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में डॉ. अतुल राय ने आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से पोषण, दिनचर्या, गर्भसंस्कार एवं स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियमित पोषण एवं स्वच्छता अपनाने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी क्रम में 13 अप्रैल को आयोजित नारी शक्ति बंदन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री के संदेश का श्रवण हितग्राही महिलाओं, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने कार्यक्रम की जानकारी दी।

पापड़ गांव में जलजीवन योजना की सप्लाई पाइप लाईन में बड़ा लीकेज, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध

सड़क पर बहता अनमोल नीर, सड़क बनी दरिया

राहौरी। जमवारामगढ़ पंचायत समिति अधीनस्थ ग्राम पंचायत पापड़ में दो दिन से जलजीवन का पानी सड़क पर व्यर्थ बहता रहता हैं। जिससे सड़क दरिया बन जाती हैं। वहीं घरों में पानी नहीं पहुंचने से ग्रामीण पेयजल को तरस रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि पापड़ गांव में शीतला माता मंदिर के पास दो दिन से जलजीवन योजना की पेयजल सप्लाई पाइप लाईन टूटी हुई हैं। सप्लाई चालू होते

ही पूरा पानी यहां पर निकल जाता हैं। जिससे सड़क दरिया बन जाती हैं। लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार लोग इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। पाईप लाईन लीकेज होने से कालिका की ढाणी की तरफ पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा हैं। जिससे ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशान होना पड़ रहा हैं। ग्रामीणों ने इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने की मांग की हैं।

ग्राम पंचायत प्रशासक ललिता देवी मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायत ने अभी जलजीवन योजना को हैंडओवर नहीं किया है। और ग्राम पंचायत इसका संचालन नहीं कर रही हैं। ग्रामीण स्वयं के स्तर पर ही इसको चला रहे हैं। इसमें पंचायत का कोई लेना देना नहीं हैं। इसकी जिम्मेदारी पीएचईडी की हैं। वहीं जलदाय विभाग के जेईएन कालूराम मीणा ने बताया कि पापड़ में जलजीवन योजना का ट्यूबवेल का दो साल से ग्राम पंचायत ही संचालन कर रही हैं। टूट फूट होने पर जिस सामान की आवश्यकता होती हैं वह उपलब्ध करा देते है।

कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले जांबाज वनरक्षक को बैतूल में दी श्रद्धांजलि

वन कर्मचारियों ने एकजुट होकर शहीद की स्मृति में किया नमन, सख्त कार्रवाई की मांग, मुरैना की घटना से प्रदेशभर में आक्रोश

बैतूल। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद हुए वनरक्षक हरकेश गुर्जर की शहादत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। मुरैना जिले के अंबाह रेंज में विगत 8 अप्रैल को कर्तव्य निभाते हुए रेत माफियाओं द्वारा उन्हें कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद प्रदेशभर में वन विभाग के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश और शोक व्याप्त है।

इसी कड़ी में वन विभाग बैतूल द्वारा वनवृत कार्यालय, तीनों वनमंडल कार्यालयों सहित ताप्ती रेंज और बैतूल रेंज में शोक श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया। सभाओं में उपस्थित वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शहीद वनरक्षक को श्रद्धांजलि अर्पित की।

वन कर्मचारियों ने कहा कि हरकेश गुर्जर ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जो पूरे विभाग के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उनकी शहादत यह दर्शाती है कि वन विभाग के कर्मचारी किस तरह जोखिम भरे हालात में भी अपने दायित्वों को निभा रहे हैं।

शोक सभाओं के दौरान कर्मचारियों ने रेत माफिया के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं वन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए संकल्प लिया कि शहीद की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक सख्ती से जारी रखी जाएगी।

भाजपा कुंभराज मण्डल ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई

कुंभराज। आज भाजपा कुंभराज मण्डल ने संविधान निर्माता, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर बाबा साहेब के विचारों को याद किया और उनके बताए गए समानता, शिक्षा और संघर्ष के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' - बाबा साहेब के इस मूलमंत्र को सभी ने दोहराया।

'बजट क्वेस्ट 2026' के द्वितीय दिवस का सफल आयोजन

केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग एवं विशेषज्ञों के साथ युवाओं का संवाद

मध्य प्रदेश में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित 'मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित दो दिवसीय कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर 'बजट क्वेस्ट 2026' का सफल एवं प्रभावी आयोजन एलएनसीटी कॉलेज, भोपाल में संपन्न हुआ। इस दिन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को देश की आर्थिक नीतियों, बजट प्रक्रिया एवं समावेशी विकास के विभिन्न आयामों से अवगत कराना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के माननीय सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉ. अनुपम चौकसे के साथ-साथ श्री किशन सिंह सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, भोपाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय अतिथियों का स्वागत राज्य निदेशक श्रीमती तारा पारगी एवं राज्य निदेशक श्री मंगलराम जाखड़ द्वारा किया गया।

अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग ने युवाओं को देश के महान महापुरुषों के उदाहरण देते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और यदि युवा सही दिशा, दृष्टि एवं संकल्प के साथ आगे बढ़ें, तो देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा युवाओं के साथ वर्चुअल संवाद रहा। अपने संबोधन में उन्होंने 'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए युवाओं को इस मंच से जुड़कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म युवाओं को कौशल विकास, स्वयंसेवा, नेतृत्व एवं नवाचार के अवसर प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयगत सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें विशेषज्ञों ने अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला।

विकसित कृषि सत्र- इस सत्र में कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक कृषि, तकनीकी नवाचार एवं किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। श्री एच. आर. प्रभाकर, सहायक निदेशक, कृषि विभाग श्री खुदीराम सनोदिया, एसडीओ, कृषि विभाग डॉ. अक्षय जैन, डायरेक्टर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एलएनसीटी कॉलेज वक्ताओं ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग, सतत कृषि पद्धतियों, नवाचार एवं युवाओं की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।

ह्यूमन कैपिटल सत्र

इस सत्र में मानव संसाधन विकास, कौशल उन्नयन एवं नीति-निर्माण के महत्व पर चर्चा की गई।

श्री मनोज कुमार जैन, वरिष्ठ सलाहकार एवं प्रमुख, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस श्रीमती रोमा बाजपेई, निदेशक (वित्त एवं प्रशासन), एसएसआर ग्लोबल स्किल्स पार्क

वक्ताओं ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसरों एवं भविष्य की अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की भूमिका पर गहन विचार साझा किए।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को बजट प्रक्रिया, सरकारी योजनाओं एवं नीति-निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही, युवाओं को यह भी बताया गया कि वे किस प्रकार 'मेरा युवा भारत' प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं।

नटखट चौक में किया पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने जनसंवाद

बैटरी ऑटो से यातायात प्रभावित सहित छेड़खानी की शिकायत

भोपाल, नप्र। भोपाल पुलिस आयुक्त संजय कुमार का लगातार भोपाल शहर के थानां क्षेत्रों में जनसंवाद जारी है। इसी कड़ी में सोमवार रात पुलिस कमिश्नर संजय कुमार थाना निशातपुरा अंतर्गत करोंद स्थित नटखट चौक पहुँचे। जहां उन्होंने आमजन से बात कर समस्याओं को सुना। जिला भाजपा उपाध्यक्ष अनुसचित जाति मोर्चा राजेश अहिवार रक्का ने बताया कि करोंद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। क्षेत्र का यातायात ठप हो गया है। इसका कारण है क्षेत्र में लगातार बढ़ती बैटरी ऑटो की संख्या। जो यातायात नियमो को ताक में रख सड़को को जाम कर सवारियां भर रहे है। जिन्हें पुलिस को भी डर नही। जो ऑटो चलाते समय व उन्हें भरते समय महिलाओं व लड़कियों के साथ हूटिंग कर छेड़खानी करते है। वही उन्होंने पुलिस कमिश्नर को नटखट चौक से लगे सेफिया कॉलेज ग्राउंड में असामाजिक तत्वों के

जमावड़ा की बात कही। जिसपर जनसंवाद के बाद पुलिस कमिश्नर सेफिया कॉलेज की बाउंडरी की टूटी दीवार से अंदर जाकर रात में ही ग्राउंड का निरक्षण किया। वही फायर फाइटर पंकज यादव ने कहा कि रुसल्ली के लिए रतन कॉलोनी से आने वाले मोड़ पर मोटर मैकेनिकों का कब्जा हो गया है। जहां से क्षेत्र ने पुराने रुसल्ली में लोगो का आना जाना भी मुश्किल हो गया है। इसी के साथ संपूर्ण करोद क्षेत्र में अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है। वही कुछ लोगो ने क्षेत्र में स्थित गुमठीयो में गांजा मिलने की बात कही। इसी प्रकार अनेको लोगो ने क्षेत्र की समस्याओं से कमिश्नर को अवगत करवाया। पुलिस कमिश्नर द्वारा लोगों की जन समस्याएं सुन अधिकारियों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। जनसंवाद के अंत में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आमजन को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई जिसमें कहा गया कि दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनेगे और कार चलाते समय बेल्ट जरुर लगाएंगे। साथ ही रेडसिग्नल को क्रॉस नहीं करेंगे। जन संवाद के दौरान पुलिस कमिश्नर संजय कुमार के साथ डीसीपी जोन04 मयूर खंडेलवाल, एसीपी निशातपुरा अक्षय चौधरी, थाना प्रभारी निशातपुरा मनोज पटवा सहित अन्य पुलिस स्टाफ मौजूद रहा।

नेहरू नगर स्थित श्रेष्ठ सेल्स सर्विस की दुकान से गैस का अंतरण की शिकायत घरेलू गैस सिलेंडर जप्त

भोपाल नप्र। खाद्य विभाग भोपाल द्वारा नेहरू नगर स्थित श्रेष्ठ सेल्स सर्विस की दुकान से घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध तरीके से गैस का अंतरण की शिकायत पर कार्यवाही कर सिलेंडर जप्त किए गए।

चंद्रभान सिंह जादौन जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अधिकारि संदीप भार्गव सहायक आपूर्ति अधिकारी, सुनील वर्मा, तृणाल जांभोलकर और वसुंधरा पेंड्रो मयंक द्विवेदी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जांच की गई। अवैध गैस रीफिलिंग की खबर पर खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु श्रेष्ठ सेल्स एंड सर्विसेज नेहरू नगर की जाँच हेतु दिनांक 11-4/2016 को उपस्थित हुए मौके से दुकान बंद और संचालक सोनू विश्वकर्मा मौके फ़ोन बंद कर फरार थे। इस दौरान दुकान को सील किया गया। पुनः संचालक सोनू से संपर्क कर और सील खोल कर दुकान के शटर खोले गए। मौके पर दुकान में 6 नग घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। जिसमे से दो

सिलेंडर में गैस भरी पाई गई। मौके पर अवैध गैस अंतरण बंसी और तौल कांटा भी पाया गया। संचालक सोनू द्वारा गैस चूल्हा विक्रेय और रिपेयर की आड़ में अवैध गैस का अंतरण भी करना स्वीकारा गया। अवैध गैस भंडारण और गैस का अंतरण पाए जाने के कारण मौके से 6 नग गैस सिलेंडर सोनू से जप्त किए गए और बीएस सर्विसेज गैस एजेंसी कोटरा के सुपुर्दगी में दिए गए।

बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया

भोपाल प्रटा। भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर ऑल इण्डिया बैंक ऑफ बडौदा एस.सी/एस.टी. एम्पलाईज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संगठन के पदाधिकारी प्रदीप चितारा, गंगा चितारा, भगवान दास ढालिया, अशोक सांकले, विहान चितारा आदि ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा पूर्वक नमन कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।

करोंद चौराहर स्थित खाटूश्याम मंदिर में ग्यारस में सजा बाबा का दरबार

भोपाल, नप्र। करोंद चौराहा हनुमान मंदिर करोंद के पास बाबा खाटूश्याम मंदिर में ग्यारस के उपलक्ष्य में हर बार की तरह सजा बाबा का दरबार। बड़ी संख्या में भक्त बाबा के दरवार में अरदास लगाने पहुँचे। ग्यारस के उपलक्ष्य में हमेशा की तरह सोमवार को भी बाबा की महाआरती कर छप्पन भोग लगाया गया। भक्तों ने विजय महाराज के साथ बाबा की श्रद्धा के साथ आरती कर अपनी अरदास बाबा के चरणों मे रखी। विजय महाराज द्वारा भक्तों को झाड़ा गया और महाआरती पश्चत भक्तों में प्रसादी वितरण की गई।

विजय महाराज ने बताया कि बाबा के दरवार में आने वाले भक्तों की परेशानी बाबा दूर करते है। उन्हें बाबा के आशीर्वाद से झाड़ा लगा उपाय बताता हू। बाबा सबपर अपनी कृपा करते है और उन्हें लाभ होता है। ये मेरे लिया गर्व की बात है। बाबा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है।

जल गंगा संवर्धन अभियान के सहभागी सभी विभाग डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से दर्ज करें जानकारी : श्रीमती रस्तोगी

भोपाल, नप्र। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। सभी विभागों के नोडल अधिकारियों को रैंकिंग के लिए बनाए गए डैशबोर्ड में अनिवार्य रूप से समय पर जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए। जिससे अभियान की प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने तथा पारंपरिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 19 मार्च से 'जल गंगा संवर्धन अभियान' संचालित किया जा रहा है। अभियान से जुड़े 18 विभागों द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संवर्धन को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, इससे प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण को नई दिशा मिल रही है। अपर मुख्य सचिव श्रीमती रस्तोगी ने 19 मार्च से अब तक किए गए कार्यों की विभाग वार प्रगति की समीक्षा कर सभी विभागों को अभियान का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद श्री अवि प्रसाद ने बैठक में सहभागी विभागों के नोडल अधिकारियों से विभागवार प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए बनाए गए डैश बोर्ड में अनिवार्य रूप से जानकारी दर्ज करें। डैश बोर्ड के माध्यम से अभियान की प्रगति की विभागवार रैंकिंग भी की जाएगी। बैठक में सहभागी विभागों द्वारा अभियान अंतर्गत संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन एवं आवास, जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उद्यानिकी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, राजस्व, संस्कृति और जन अभियान परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

एमपी के कई जिलों में भीषण लू का अलर्ट

भोपाल । मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों तक आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला, लेकिन अब प्रदेश में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा और कई जिलों में लू चलने की स्थिति बन सकती है।

कमजोर मौसम सिस्टम से नहीं मिलेगी राहत : 15 अप्रैल से एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, लेकिन यह काफी कमजोर रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तापमान में किसी खास गिरावट की उम्मीद नहीं है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आमतौर पर गर्मी अपने चरम पर पहुंचती है और इस बार भी यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है।

प्रदेश में बढ़ता तापमान और गर्मी का असर

सोमवार को रतलाम प्रदेश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके अलावा धार, नर्मदापुरम और खरगोन जैसे जिलों में भी पारा 40 डिग्री के पार चला गया। यह संकेत है कि प्रदेश अब तेजी से हीटवेव की ओर बढ़ रहा है।

16 और 17 अप्रैल से लू की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट जिलों में लू चल सकती है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे दिन के समय लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी।

बारिश के बाद अब गर्मी का दौर

अप्रैल की शुरुआत में प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदला हुआ था। 1 से 9 अप्रैल के बीच कई जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई। 45 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि 15 से ज्यादा जिलों में ओले गिरे। ग्वालियर में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि अब यह दौर खत्म हो चुका है और मौसम पूरी तरह गर्मी की ओर बढ़ गया है।

बड़े शहरों में गर्मी का ट्रेंड

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में अप्रैल के दूसरे हिस्से में तापमान तेजी से बढ़ता है। पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार भोपाल और इंदौर में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचता है, जबकि जबलपुर में 44 डिग्री और ग्वालियर में 45 डिग्री के पार जाने का रिकॉर्ड है।

भोपाल में रिकॉर्ड गर्मी और बारिश

भोपाल में 29 अप्रैल 1996 को तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं इस महीने में अचानक बारिश और आंधी भी देखने को मिलती है। 2013 में एक ही दिन में 30 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 2023 में भी अच्छी वर्षा हुई थी।

इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर का मौसम रिकॉर्ड

इंदौर में अप्रैल के दौरान तापमान 44.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। जबलपुर में 1970 में 45.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। ग्वालियर प्रदेश का सबसे गर्म शहर माना जाता है, जहां तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका है।

प्रीमियम ट्रेन में PNR आधारित कैटरिंग व्यवस्था, एक टिकट होने पर सभी को लेना होगा भोजन

यात्रियों की बढ़ी परेशानी

भोपाल। वंदेभारत, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में कैटरिंग व्यवस्था में हुए बदलाव ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब एक पीएनआर या एक टिकट पर यात्रा कर रहे सभी यात्रियों को सामूहिक रूप से भोजन लेना अनिवार्य होगा। यानी यदि एक भी यात्री भोजन लेने से मना करता है, तो पूरे समूह को भोजन की सुविधा नहीं मिलेगी। इस फैसले से खासकर परिवार और समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

पीएनआर आधारित कैटरिंग व्यवस्था लागू : रेलवे ने यह नई व्यवस्था पीएनआर आधारित कैटरिंग के रूप में लागू की है। पहले जहां यात्री अपनी व्यक्तिगत पसंद के अनुसार भोजन ले सकते थे। अब पूरी टिकट पर एक समान निर्णय लागू होगा। इससे उन यात्रियों को परेशानी हो रही है, जो अलग-अलग खानपान की पसंद रखते हैं।

यात्रियों को मजबूरी में करना पड़ रहा ऑर्डर : भोपाल के एक यात्री ने बताया कि उन्हें यात्रा के दौरान दो लोगों के लिए ही भोजन चाहिए था, लेकिन नियम

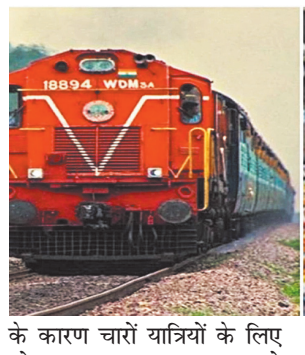

के कारण चारों यात्रियों के लिए भोजन बुक करना पड़ा। इससे अनावश्यक खर्च भी बढ़ रहा है। भोजन की बर्बादी भी हो रही है।

ऑनलाइन बुकिंग में भी आ रही दिक्कतें : यात्रियों का कहना है कि ऑनलाइन फूड बुकिंग के दौरान भी सिस्टम एक ही विकल्प दिखा रहा है। यदि सभी यात्रियों के लिए भोजन चयन नहीं किया जाता, तो ऑर्डर स्वीकार नहीं होता। इससे कई बार यात्रियों को भोजन बुक करने में परेशानी होती है।

प्रदेश पुलिस की आधुनिक तकनीक से अंतर्राज्यीय सायबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही

भोपाल, नप्र। आधुनिक तकनीक, त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली एवं सुनियोजित रणनीति के माध्यम से मध्यप्रदेश पुलिस लगातार सायबर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। पुलिस ने देवास और विदिशा में सायबर अपराधों के विरुद्ध अलग-अलग प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सायबर ठगी में संलिप्त आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कीगयी। देवास में 'e-Zero FIR के तहत अंतर्राज्यीय सायबर ठग गिरोह का पर्दाफाशः जिले में दिनांक 02 जनवरी को दर्ज एक प्रकरण में फरियादी के मोबाइल पर 'RTOChalan. apk 'नामक संदिग्ध लिंक भेजकर मोबाइल हैक कर 7 लाख 98 हजार रुपए की ठगी की गई थी। प्रकरण में थाना नाहर दरवाजा में अपराध पंजीबद्ध कर तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस टीम द्वारा 1600 किलोमीटर दूर हावड़ा (पश्चिम बंगाल) एवं 800 किलोमीटर दूर दिल्ली से जुड़े संगठित गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख 96 हजार 500 रुपए नगद एवं 02 एंड्रॉइड मोबाइल फोन जप्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लागू 'e- ZeroFIR प्रणाली के अंतर्गत 1,00,000/- से अधिक की सायबर ठगी की शिकायत 1930 हेल्पलाइन अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज होते ही स्वतः सायबर मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध की जाती है, जिसे संबंधित जिले में जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज कर त्वरित विवेचना प्रारंभ की जाती है।

गृह विभाग की गाइडलाइन

जनगणना में महिला का नाम बताने के लिए परिवार को बाध्य नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

भोपाल। मध्य प्रदेश में आगामी जनगणना को लेकर गृह विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारी किसी परिवार के सदस्य को महिला का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे।

जनगणना के दौरान गलत जानकारी देने या कार्य में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, तो दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

दो चरणों में होगी जनगणना : राज्य में जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण एक से 30 मई के बीच होगा, जिसमें मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के लिए गृह विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

कर्मचारियों को दिए गए विशेष अधिकार : दिशा-निर्देशों के अनुसार, जनगणना कर्मचारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रश्न पूछ सकेंगे और नागरिकों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कर्मचारी घर, परिसर या अन्य स्थानों में प्रवेश कर आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकेंगे, बशर्ते वह स्थान प्रतिबंधित श्रेणी में न आता हो।

बाधा डालने पर होगी कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति जनगणना कार्य में बाधा उत्पन्न करता है या कर्मचारियों को जानकारी एकत्र करने से रोकता है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।

अभिलेखों की जांच का भी अधिकार

कर्मचारियों को संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार भी दिया गया है, ताकि जनगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके।

संपादकीय

केन-बेतवा परियोजनाः विकास बनाम विस्थापन का गहराता द्वंद्व

छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना को लेकर संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर आदिवासी और ग्रामीण समुदाय 'जल, जंगल, जमीन' की रक्षा के लिए 'मिट्टी सत्याग्रह' और भूख हड़ताल जैसे मार्मिक विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन सहमति और मुआवजे के आधार पर पुनर्वास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का दावा कर रहा है। यह टकराव विकास और मानवीय अधिकारों के बीच संतुलन की जटिल चुनौती को उजागर करता है।

विजावर क्षेत्र में केन नदी किनारे सैकड़ों लोग तपती धूप में डटे हुए हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे न केवल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बचाने की भी जिद पर अड़े हैं। भूख हड़ताल और 'आकाश सत्याग्रह' के चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, जिससे स्थिति चिंताजनक हो गई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजा और पुनर्वास के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि 14 मकान सहमति से हटाए गए हैं और किसी भी परिवार को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। चरणबद्ध पुनर्वास और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का दावा भी किया जा रहा है।

केन-बेतवा परियोजना बुंदेलखंड के जल संकट के समाधान के रूप में देखी जा रही है, लेकिन इसके साथ जुड़े विस्थापन और पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

स्पष्ट है कि विकास की इस राह में संवाद, पारदर्शिता और न्यायपूर्ण पुनर्वास ही समाधान का आधार बन सकते हैं, अन्यथा यह संघर्ष और गहराता जाएगा।

कुचलना होंगे देश में पनपते आतंकवादी समूह

अतीत गवाह है कि ईश निंदा के मनगढन्त आरोप लगाकर सर तन से जुदा करने वाली प्रायोजित भीड एकत्रित की जाती है और फिर पूर्व नियोजित षडयंत्र को अमली जामा पहना दिया जाता है। राष्ट्रविरोधी ताकतें सीमापार से मिलने वाले धन से कट्टरता को पोषित कर रहीं हैं, भय का वातावरण निर्मित कर रहीं है और बना रहीं है आन्तरिक युद्ध के हालात। देश के लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में वैमनुष्यता का जहर फैल चुका है जिसे खास धार्मिक स्थानों से निरंतर संरक्षण दिया जा रहा है। हर जगह अवसरवादियों की जमातें मौके की तलाश में हैं।

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

वर्तमान परिस्थितियों से समूचा संसार जूझ रहा है। पाकिस्तान में हुई शान्ति वार्ता का विफल होना एक नये संकट का शंखनाद माना जा रहा है। ईरान संरक्षित हिजबुल्लाह, हूती, हमाज जैसी दहशतगर्द जमातें खुलेआम मिसाइल, ड्रोन और राकेट लांचर सहित अत्याधुनिक हथियारों से हमले कर रहे हैं। आतंक परस्त देशों के कवच में कट्टरपंथी जमातें दहशतगर्दों की फौजें तैयार करने में जुटे हैं। अमन, चैन, भाईचारे को गजवा-ए-दुनिया निगलती जा रही है। कहीं यहूदियों को समाप्त करने की धमकियां दी जा रहीं हैं तो कहीं हिन्दुओं को। ईसाई और पारसियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह हालात दुनिया के साथ-साथ देश के अन्दर भी बेलगाम होते जा रहे हैं। अतीत गवाह है कि ईश निंदा के मनगढन्त आरोप लगाकर सर तन से जुदा करने वाली प्रायोजित भीड एकत्रित की जाती है और फिर पूर्व नियोजित षडयंत्र को अमली जामा पहना दिया जाता है। राष्ट्रविरोधी ताकतें सीमापार से मिलने वाले धन से कट्टरता को पोषित कर रहीं हैं, भय का वातावरण निर्मित कर रहीं है और बना रहीं है आन्तरिक युद्ध के हालात। देश के लगभग प्रत्येक शहर, कस्बे और गांव में वैमनुष्यता का जहर फैल चुका है जिसे खास धार्मिक स्थानों से निरंतर संरक्षण दिया जा रहा है। हर जगह अवसरवादियों की जमातें मौके की तलाश में हैं। किसी भी मनगढन्त मुद्दे को सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाकर देश भर में अशान्ति फैलाने के निरंतर प्रयास होते रहे हैं जिस पर उत्तरदायी तंत्र द्वारा हमेशा ही बेखबर होने का ढोंग रचा जाता रहा है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके मकान, दुकान, कारखाने लगाये जा रहे हैं। इन अवैध निर्माणों को सोची समझी योजना के तहत सकरी गलियों में बहुमंजिला इमारतें के साथ तैयार किया जाता है ताकि सुरक्षाबलों की आमद के दौरान आक्रमण की व्यूह रचना का लाभ उठाया जा सके। देश की लगभग हर बसाहट में खास झंडा लगाकर अपनी उपस्थिति, कट्टरता और एकता का सबूत देने वाले

जुल्म की नई इबारत लिखने में लगे हैं जिस पर कार्यपालिका जानबूझकर मौन धारण रखे हुए है। इन अवैध परिसरों में अवैध ढंग से विद्युत, जल और शासकीय सुविधाओं का खुलकर निःशुल्क उपयोग हो रहा है। ऐसे लगभग सभी स्थानों पर स्थानीय निकायों ने सुविधाओं का अम्बार भी लगा दिया है। जनप्रतिनिधियों ने वोट बैंक के लिए अनेक अवैध निर्माणों को वैध कराना भी शुरू कर दिया है। इन स्थानों को अभेद किले के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है जो आने वाले समय में आक्रमण का केन्द्र बनेंगे। इन स्थानों पर भारी मात्रा में अवैध असलहे, गोला-बारूद और घातक संसाधन मौजूद होने की खबरें भी निरंतर आ रहीं हैं। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाली अनेक पाठशालाओं में जहरीली पौध तैयार की जा रही है। लगभग हर आबादी में ऐसे आतंकी संगठन मौजूद है जिन्हें खूनी खेल खेलने में महारत हासिल है। अनेक राजनैतिक दलों के कद्दावर नेताओं से लेकर लालफीताशाही की एक खास विरादरी खुलकर उनके साथ खडी दिखती है। नियम, कानून और कायदे केवल निरीह, गरीब और लाचार तक ही सीमित होकर रह गये हैं या फिर जुल्मी को बचाने हेतु संविधान की धारायें प्रयुक्त होतीं हैं। भीड तंत्र के आगे कार्यपालिका और विधायिका पूरी तरह नतमस्तक हो चुकी है। वोट बैंक बढाने की मानसिकता अब दावानल बनकर उभर चुकी है। आश्चर्य है कि धरातल की वास्तविक स्थिति को नजरंदाज करते हुए चुनावी धरातल पर मुफ्तखोरी की निरंतर घोषणायें हो रहीं हैं। ऐसे राजनैतिक दलों को अपने घोषणा-पत्रों की पूर्ति हेतु पार्टी फंड से खर्च करना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि जनता पर टैक्स का दबाव बढाकर हरामखोरों की फौज तैयार करके उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों हेतु सुगम समय प्रदान करने वाले राजनैतिक दल ही सत्ता सुख की चाह में आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। वातानुकूलित संस्कृति में पलने वाला कार्यपालिका का ऊपरी तंत्र अब नित नये नियम, कानून बनाकर धरातली कर्मचारियों की मुश्किलें बढा रहे हैं और नागरिकों का कर रहे हैं जीना हराम। जमीन पर काम करने वाले एक कारिन्दा को नियंत्रण करने के लिए दर्जन भर मोटी पगार वाले बडे साहब बैठाये गये हैं जो स्वयं के कर्तव्यों की पूर्ति हेतु संविदाकर्मियों का खून पी रहे हैं। उनके लिए मौज, मस्ती और मसखरी ही जीवन का उद्देश्य बन गया है। देश के आन्तरिक हालातों को उत्तरदायी तंत्र में बैठे जिम्मेवार लोग किन्हीं खास कारणों से निरंतर अदृष्टिगत करते चले जा रहे हैं। उधार लेकर घी पीने वाले तंत्र के आन्तरिक हालात बद से बद्तर हो चुके हैं मगर सत्ता हथियाने के लिए कभी लैपटाप बांटे जाते हैं तो कभी स्कूटी। कभी मोबाइल फोन तो कभी नगद धनराशि। किसी को तीर्थयात्रा कराई जाती है तो किसी को हज के लिए अनुदान। कहीं वक्फ को सम्पत्तियां आवंटित हो रहीं है तो कहीं ट्रस्टों को। कोई योजनाओं के नाम पर संस्थानों को खुली लूट का सुअवसर दे रहा है तो कोई सर्विस प्रोवाइडर को प्रमोट करके सरकारी दस्तावेजों में सेंध लगाने का मौका। ऐसे में यदि देश में पनपते आतंकवादी समूहों को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले समय को सुखद कदापि नहीं कहा जा सकेगा। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

वैसाखी – आगे बढ़ने का साहस

आज हम तीन ऐसी महान आत्माओं को स्मरण करते हैं—तीनों अलग प्रकार के साहस के प्रतीक, और इस सत्य के प्रमाण कि दृढ़ विश्वास के साथ जिया गया एक जीवन राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। आओ, तुम्हें उनके बारे में बताऊँ।

जी एस यादव

1699 की वसंत ऋतु में पंजाब के खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहे थे। आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह एक विशाल सभा के सामने खड़े थे। उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी भीड़ को मौन कर दिया–

'कौन है जो अपने विश्वास के लिए सब कुछ–यहाँ तक कि अपना जीवन भी–अर्पित कर सकता है? '

एक व्यक्ति आगे आया। फिर दूसरा। फिर तीन और। ये पाँच–पंज प्यारे–खालसा के बीज बनेः एक ऐसा समुदाय जो जन्म या पद से नहीं, बल्कि साहस, समानता और सत्य पर आधारित था।

उस दिन से वैसाखी केवल फसल का त्योहार नहीं रही। वह एक स्मरण बन गई–कि साधारण लोग, जब असाधारण पुकार का उत्तर देते हैं, तो दुनिया को बदल सकते हैं।

आज भी हर अप्रैल खेत सुनहरे होते हैं। और वह प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है।

सर एम. विश्वेश्वरैया – निर्माण का साहस

इसी दिन हम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भी याद करते हैं–एक ऐसे अभियंता, जिन्होंने संसाधनों की कमी वाले भारत को देखकर प्रतीक्षा करने के बजाय निर्माण का मार्ग चुना।

उनकी सबसे बड़ी देन कृष्णा राजा सागर बाँध रही, जिसने सूखी भूमि को उपजाऊ बनाया और लाखों लोगों को जल उपलब्ध कराया। पर उनका सबसे बड़ा विश्वास यह था कि भारत का

भविष्य केवल प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि विज्ञान, योजना और अनुशासित प्रयास से बनेगा।

उन्होंने नब्बे वर्ष की आयु तक भी उसी अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य किया। उनका साहस युद्ध का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि का साहस था–ऐसी व्यवस्थाएँ बनाने का, जो पीढ़ियों तक जीवित रहें।

उन्होंने सिखाया कि सच्ची प्रगति एक-एक सोच-समझकर लिए गए निर्णय से बनती है।

डॉ. बी.आर. आंबेडकर – उठने और उठाने का साहस

आज हम भीमराव रामजी आंबेडकर की 135वीं जयंती भी मना रहे हैं–एक ऐसे व्यक्ति की, जिसे परिस्थितियाँ तोड़ सकती थीं, पर उन्होंने स्वयं को नहीं, बल्कि समाज को पुनः गढ़ना चुना।

गहरे भेदभाव में जन्मे, उन्हें वे सामान्य अधिकार भी नहीं मिले जो दूसरों को सहज प्राप्त थे। पर हर अन्याय उनके लिए ऊर्जा बन गया। अथक परिश्रम और अटूट इच्छाशक्ति से उन्होंने विश्व के श्रेष्ठ संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की–अपने लोगों से दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए सशक्त बनकर लौटने के लिए।

उन्होंने केवल अपने लिए संघर्ष नहीं किया, बल्कि उन सभी के लिए लड़े जिन्हें कभी यह कहा गया कि उनका कोई मूल्य नहीं। और जब स्वतंत्र भारत को संविधान की आवश्यकता थी, तो आंबेडकर ने उसे उसका नैतिक आधार दिया–न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व–वे मूल्य जो आज भी देश को जोड़े रखते हैं।

उनका जीवन एक महान संदेश देता है–सच्ची महानता अकेले आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि दूसरों को साथ उठाने में है।

तीन व्यक्तित्व। तीन अलग क्षेत्र। पर एक ही सूत्र–उद्देश्य से निर्देशित जीवन वह छाप छोड़ता है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता।

भारतीय संगीत की सरस्वती-सुरधारा मौन हो गईं

(प्रणय विक्रम सिंह)

स्वर जब साधना बन जाए और साधना जब संवेदना में ढलकर पीढ़ियों के हृदय में घर कर ले, तब वह केवल संगीत नहीं रहता, वह संस्कृति बन जाता है।

'पद्म विभूषण' से अलंकृत महान गायिका आशा भोसले जी का निधन इसी सांस्कृतिक चेतना की एक अमिट धारा के अवसान का क्षण है।

आशा ताई केवल एक स्वर नहीं थीं, वे भारतीय संगीत की वह विस्तृत यात्रा थीं, जिसमें समय, समाज और संवेदना एक साथ बहते रहे। उनके गीतों में जीवन के हर रंग थे। यौवन की चंचलता, प्रेम की मधुरता, विरह की वेदना और संघर्ष की सघनता की हर छटा व्याप्त थी। उन्होंने जिस सहजता से विविध भावों को अपने स्वर में पिरोया, वह उन्हें असाधारण बनाता है। मराठी फिल्म 'माझा बाल' (1943) में गाया गया उनका पहला गीत 'चला चला नाव वाला' और हिंदी सिनेमा में 'चुनरिया' (1948) का 'सावन आया', केवल आरंभ नहीं थे, बल्कि उस अनवरत साधना के प्रथम स्वर थे, जिसने आने वाले दशकों तक संगीत को नई ऊंचाइयां दीं।उनकी गायकी का विस्तार इतना व्यापक था कि वह किसी एक शैली, भाषा या युग की सीमा में बंधकर नहीं रह सकी।20 से अधिक भारतीय भाषाओं में 11 हजार से भी अधिक गीतों को अपनी आवाज देने वाली आशा जी ने संगीत को सचमुच बहुभाषी और बहुरंगी बना दिया। यही नहीं, उनके इस अद्भुत योगदान ने उन्हें वर्ष 2011 में सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिलाया। उनकी प्रतिभा की गूंज केवल भारत तक सीमित नहीं रही। वर्ष 2005 में ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नामांकन पाने वाली वह पहली भारतीय महिला गायिका बनीं। यह उपलब्धि उनके स्वर की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है।शास्त्रीयता की गहराई से लेकर आधुनिकता की गति तक, उन्होंने हर आयाम को अपनी स्वर-साधना से स्पर्श किया। यही कारण है कि उनके गीत केवल सुने नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। वे स्मृतियों में बसते हैं और समय के साथ और अधिक अर्थवान होते जाते हैं। 'दम मारो दम' और 'पिया तू अब तो आजा' जैसे गीतों ने उस दौर में नई अभिव्यक्ति का साहस दिया। वे केवल गाने नहीं थे, बल्कि बदलते समाज की धड़कन थे। यद्यपि इन गीतों को लेकर विवाद भी हुए, किंतु यही विवाद उनकी निर्भीक कला-साधना और प्रयोगधर्मिता का प्रमाण बन गए। आशा जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने संगीत को केवल कला के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव के रूप में जिया। उनके स्वर में एक जीवंतता थी, जो श्रोताओं को सीधे उनके भाव-जगत से जोड़ देती थी। वह आवाज कभी थकती नहीं थी, वह हर दौर के साथ स्वयं को नया रूप देती रही और यही उनका चिरंतन आकर्षण था। उनका जाना एक कलाकार का जाना भर नहीं है, यह उस युग का अवसान है, जिसने भारतीय संगीत को विश्व पटल पर एक विशिष्ट पहचान दी। परंतु उनकी विरासत उनके गीतों में, उनके सुरों में और उन अनगिनत हृदयों में जीवित रहेगी, जिन्हें उन्होंने स्पर्श किया। आज जब वह स्वर मौन हुआ है, तब भी उसकी गूंज शाश्वत है। वह गूंज हमें यह स्मरण कराती रहेगी कि कला कभी समाप्त नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है और महान कलाकार अपने पीछेएक ऐसा आकाश छोड़ जाते हैं, जिसमें उनके सुर सदैव झंकृत होते रहते हैं।

कूटनीति के जरिए पेट्रोलियम आपूर्ति को रखा बरकरार

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरी दुनिया की चिंता ऊर्जा को लेकर थी। आज की दुनिया ऊर्जा के लिए जीवाश्म तेलों पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जिसे हम पेट्रोल और डीजल के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी आज ऊर्जा की बड़ी स्रोत है। ईरान पर हमले के पहले बहुत लोगों ने होमुर्ज जलडमरूमध्य का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज हर पढ़ा-लिखा और सचेत शख्स इसे जान गया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा है। इसके जरिए पूरी दुनिया को आपूर्ति होने वाला बीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ इसी रास्ते से गुजरता रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान पर हमले के पहले तक भारत आयात होने वाले कच्चे तेल के आधे हिस्से की आपूर्ति इसी रास्ते होती थी। इससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक थी। लेकिन भारत ने ना सिर्फ होमुर्ज के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाए रखने की कूटनीतिक कोशिशें जारी रखीं, बल्कि वैकल्पिक रास्ते की भी तलाश तेज कर दी।

(अमेश चतुर्वेदी)

भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का करीब 85 फीसद हिस्सा आयात करता है। इसका आधा हिस्सा होमुर्ज के रास्ते ही आता था। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार होमुर्ज के रास्ते भारत रोजाना ढाई से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता था। लेकिन ईरान पर हमले के बाद यह घटकर इसका आधा ही रह गया है।

28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद पूरी दुनिया की चिंता ऊर्जा को लेकर थी। आज की दुनिया ऊर्जा के लिए जीवाश्म तेलों पर सबसे ज्यादा निर्भर है, जिसे हम पेट्रोल और डीजल के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही प्राकृतिक गैस भी आज ऊर्जा की बड़ी स्रोत है। ईरान पर हमले के पहले बहुत लोगों ने होमुर्ज जलडमरूमध्य का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज हर पढ़ा-लिखा और सचेत शख्स इसे जान गया है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान का कब्जा है। इसके जरिए पूरी दुनिया को आपूर्ति होने वाला बीस प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ इसी रास्ते से गुजरता रहा है। जहां तक भारत का सवाल है तो ईरान पर हमले के पहले तक भारत आयात होने वाले कच्चे तेल के आधे हिस्से की आपूर्ति इसी रास्ते होती थी। इससे भारत की चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक थी। लेकिन भारत ने ना सिर्फ होमुर्ज के जरिए अपनी आपूर्ति को बनाए रखने की कूटनीतिक कोशिशें जारी रखीं, बल्कि वैकल्पिक रास्ते की भी तलाश तेज कर दी।

भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों का करीब 85 फीसद हिस्सा आयात करता है। इसका आधा हिस्सा होमुर्ज के रास्ते ही आता था। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार होमुर्ज के रास्ते भारत रोजाना ढाई से 2.7 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता था। लेकिन ईरान पर हमले के बाद यह घटकर इसका आधा ही रह गया है। वैसे तो होमुर्ज पर ओमान का भी दावा माना जाता है, लेकिन हकीकत में इस जलमार्ग पर पूरी तरह ईरान का दबदबा है। हमले के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस रास्ते पर ना सिर्फ निगरानी बढ़ा दी है, बल्कि सीमित आवाजाही हो ही मंजूरी दी है।

भारत को इसकी आशंका थी, इसलिए उसने खाड़ी के देशों से तेल आयात के लिए वैकल्पिक मार्गों पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। संकट के क्षण में भले ही ईरान ने भारत के प्रति सहयोगी रूख अख्तियार कर रखा है, लेकिन भारत ने 'केप ऑफ गुड होप' यानी अफ्रीका के दक्षिण से गुजरने वाले जलमार्ग का भी उपयोग बढ़ा दिया है। इस बीच भारत ने कूटनीतिक प्रयास जारी रखा। इसका असर यह हुआ कि ईरान भारतीय जहाजों को होमुर्ज से गुजरने की अनुमति दे रहा है। एलपीजी लदा एक जहाज कोचीन आ चुका है और ऐसे ही कुछ और जहाज तेल और गैस लेकर भारत आ रहे हैं।

इस बीच भारत ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों को अपनी नौसेना के जरिए सुरक्षा दे रहा है। भारत सरकार के अनुसार, भारतीय रिफायनरियों के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। इस बीच भारत ने रूस से भी कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ा दी है। इसका असर यह हुआ है कि भारत में जिस तरह की महंगाई की आशंका थी, वैसी नहीं दिखी। हालांकि उद्योगों के लिए आपूर्ति किए जाने वाले व्यवसायिक गैस सिलिंडर की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और व्यवसायिक गैस की आपूर्ति कम होने के चलते खाने-पीने वाली चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। महानगरों में सर्वसुलभ ठेले की चाय की कीमतें डेढ़ गुनी तक बढ़ चुकी हैं। लेकिन आपूर्ति श्रृंखला जारी रहने के चलते स्थिति खराब नहीं हुई है। जबकि पड़ोसी पाकिस्तान में आधी गाड़ियों को ही सड़कों पर उतरने की अनुमति है, वहां पेट्रोल भारत के मुकाबले करीब ढाई गुनी ऊंची दर पर मिल रहा है।

पश्चिम एशिया में संकट शुरू होने के बाद कूटनीति की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभालते हुए युद्ध शुरू होने के महज 48 घंटों के भीतर आठ खाड़ी देशों संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत,ओमान, कतर, जार्डन, ओमान, बहरीन और इजरायल के नेताओं से बात की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रां और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम से बात की। इस बातचीत का मकसद वैश्विक हालात पर चर्चा के साथ ही भारतीय हितों को सुनिश्चित करना भी था। इस बीच 'गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल' के महासचिव जासेम मोहम्मद अल बुदैवी से फोन पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बात की है। इस बातचीत का मकसद खाड़ी देशों के इस संगठन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के साथ ही भावी ऊर्जा संकट से भारत को मुक्ति दिलाने को लेकर रणनीति बनाना भी है। इसके पहले मंत्री हरदीप पुरी ने कतर की यात्रा की थी। दरअसल भारत इन देशों से भी पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बढ़ाना चाहता है। भारत की कोशिश ईरान के विकल्प के रूप में अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों का भी सहयोग हासिल करने की है।

भारत को अपनी खेती के लिए रासायनिक खाद की भी जरूरत पड़ती है। भारत में खाद उत्पादन के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बेशक रूस से भारत को कच्चा तेल और खाद की सामग्री मिल रही है, लेकिन भारत की कोशिश आपूर्ति को विविधरंगी बनाए रखना है। इसकी वजह यह है कि किसी एक देश पर किसी खास आयात के लिए पूरी तरह निर्भर होना भविष्य में ब्लैकमेलिंग की वजह बन सकता है। भारत के पास आज करीब साठ करोड़ का ऐसा विशाल मध्य वर्ग है, जिसकी खरीद क्षमता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शायद ही कोई उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादक देश ऐसा होगा, जिसे भारत की जरूरत महसूस नहीं होगी। लेकिन भारत की अपनी जरूरतें भी हैं और यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में अगर किसी चीज की गंभीर कमी होती है तो अफरातफरी का माहौल उत्पन्न होना आसान हो जाता है। इससे महंगाई भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ने से लोक के बीच नाराजगी बढ़ती है और फिर यह गुस्सा राज व्यवस्था के खिलाफ आंदोलनों के रूप में मुखर होता है। तेल और ईरान संकट को देखते हुए भारत ने कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए जिस तरह अपनी जरूरतों के लायक आपूर्ति का संतुलन बनाए रखा है, वह गौर करने लायक है। लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

डॉ, बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती धुमधाम से मनाई गई, हजारों की संख्या में अनुयाई महू पहुंचे

बौद्ध वंदना के साथ बाबा साहेब को गॉड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया, इस अवसर पर समारक से जमकर आतिश बाजी की गई, इस दौरान स्मारक सोसाइटी के सचिव राजेश वानखेड़े द्वारा मंच से बाबा के दर्शन करने आए अनुयाइयों से अभद्रता की गई । जिला प्रशासन को छीनना पड़ा माइक

इंदौर/डॉ. आंबेडकर नगर(महू)। राष्ट्रीय धरोहर, भीम जन्मभूमि स्मारक पर रात्रि ठीक 12 बजे हजारों की संख्या में अनुयाई पहुंचे और बाबा साहेब को शीश नवाया महाराष्ट्र से आए समता सैनिक दल व हजारों अनुयाइयों ने बौद्ध वंदना कर गॉड ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया इस अवसर पर जमकर आतिश बाजी की गई। इसी दौरान सलामी एवं मानवंदना के लिए उमड़ी भीड़ से एक बार फिर विवाद की स्थिती बन गई । जानकारी के अनुसार स्मारक की देख रेख के लिए बनाई गई आंबेडकर मेमोरियल सोसायटी के सदस्यों में विवाद चल रहा है। जिसकी सुनवाई उच्य न्यायालय में चल रही है। वहीं दूसरी और स्मारक के पास मंच और डोम, लगाने से आने वाले सैकड़ों महिलाओं, बच्चों, बूढ़े अनुयायियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अनुयाइयों को ठीक से दर्शन तक नहीं होते जिसके लिऐ इंदौर जिला कलेक्टर को हजारों अनुयाइयों की सुविधा को देखते हुवे एक लिखित ज्ञापन दिया गया था। जिसमे स्मारक के पास मंच और डोम नहीं लगाए जानें की गुहार लगाई गई थीं। बाऊजुद इसके दो दिन पहले से ही डोम लगाए जाने के लिए मुख्य महू पीतमपुर मार्ग को बंद कर दिया गया।

स्मारक के पास लगे मंच और डोम से बाबा साहेब की स्मारक पर उमड़ी भीड़ से अफरा तफरी मच गई। ऐसा कहा जा रहा है की राजेश वानखेड़े ने अपने राजनेतिक फायदे

हेतू स्मारक के पास मंच और डोम लगाया गया है जिस से निर्मित हुई स्थिती अव्यवस्था में बदल गई। राजेश वानखेड़े ने सीधे उकसाने वाले लहजे में मंच से अपने अहंकार का प्रदर्शन किया। जिस पर पुलिस कप्तान ने सचिव राजेश वानखेड़े के हाथों से माइक छीन कर मामला शांत कराया और अनुयाइयों को समझाइश दी ।

सलामी कार्यक्रम और आतिशबाजी के बाद लौटते हुए निकासी की उचित व्यवस्था के अभाव और अनुचित बेरिकेडिंग से आवागमन के मार्ग पर भीड़ का भारी दबाव बढ़ा, जिसके चलते समता सैनिक दल के जवानों को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा।

अपने अनुषांगिक संगठनों और सहयोगियों की हौंसला अफजाई की बजाए राजेश वानखेड़े ने जानबूझकर निशाना बनाकर लगभग ललकारने वाले लहजे में पुलिस और प्रशासन के सामने सार्वजनिक मंच से भीड़ में फंसे लोगों और अनुयायियों को अपमानित किया।

विश्व की सबसे बड़ी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्मारक की गरिमा को ताक पर रखकर सार्वजनिक मंच से सचिव राजेश वानखेड़े की बौखलाहट के समय एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहें। जिसके बाद परिस्थिति को गंभीर होता देख पुलिस के उच्च अधिकारी ने राजेश वानखेड़े के हाथों से माइक छीन लिया और स्थिति को संभाला और सभी अनुयाइयों को समझाइश दी जिसके बाद समता सैनिक दल और अनुयाइयों ने गंभीर होती स्थिति में भी संयम रखते हुए खुद को और फंसे हुए लोगों को निकालकर आवागमन को सुचारू किया।

इस घटना से अनुयायियों में गहरा रोष व्याप्त है। जिसके बाद स्मारक के बाहर निर्मित गेट पर बौद्ध भिक्षुओं के अपमान के विरोध में अनुयायियों को आवाज उठानी पड़ी और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मध्यस्थता करने आना पड़ा। पूरे मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया उसके बाद मामला शांत हो सका।

कोलार ब्लॉक कांग्रेस ने किया डॉ बाबा साहब अंबेड़कर जयंती पर माल्यार्पण

भोपाल। भारतवर्ष के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर कोलार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजवीर बुद्ध विहार,ओमनगर मे डॉ बाबा साहब अंबेड़कर जी की प्रतिमा पर कोलार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़ एवं पूर्व सरपंच मंगल सिंह यादव द्वारा माल्यार्पण

कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए एवं महिलाओ द्वारा वंदना कर आराधना की गई. इस अवसर पर कोलार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह राठौड़, पूर्व सरपंच मंगल सिंह यादव,राजवीर बुद्ध विहार के विनोद वासनिक, गुड्डू मनोहर,प्रदेश सचिव राजकुमार सिंह, चम्पालाल मीना द्य, गायत्री शर्मा, नवल सोनी, विजय वर्मा, ओमप्रकाश अहिरवार, रत्ना ताई,शाहिद हुसैन, आनंद खरे,प्रवीण वर्मा, रघुनाथ चौरे द्य, सुनील पाटिल आदि उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने सुनाई खरी-खोटी, विधायक बोले- विरोध ही कर लो

नर्मदापुरम, (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के बनखेड़ी के ग्राम मल्काजरा रविवार को पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी और जनता के बीच सीधा टकराव हुआ। रोड, नाली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक को घेर खूब खरी खोटी सुनाई। इस पर विधायक भी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा अब आप विरोध ही कर लो। गांव मल्काजरा में विधायक के विरोध के वीडियो आज सोशल मीडिया पर सामने आया है। विधायक ठाकुरदास नागवंशी, अपनी पत्नी और भाजपा पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि के साथ ग्राम मल्काजरा में गांव चले अभियान के तहत एक रोड का भूमिपूजन करने पहुंचे थे। विधायक के पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक ठाकुर दास का विरोध शुरू कर दिया।ग्रामीण पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर नाराज थे। ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध करने पर विधायक ठाकुर दास नाराज हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ने और उंगली दिखाते हुए बोले 'आप लोग विरोध ही करते रहो...' विधायक के इस बयान के बाद मौके पर माहौल और ज्यादा खराब हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याएं लंबे समय से जस की तस बनी हुई हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। एक ग्रामीण यह भी कहते सुनाई दें रहा कि आपको चार बार वोट देकर जीता रहे, विधायक बना रहे। पर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

विधायक की पत्नी और महिलाओं को घेरा

ग्रामीणों ने विधायक की पत्नी और महिला समर्थकों जिस गाड़ी से गए थे। उसे भी ग्रामीणों ने घेर लिया। उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक ठाकुरदास नागवंशी ने कहा हम रोज क्षेत्र के दौरे पर रह रहे है। रविवार को मल्काजरा गांव हुए थे। जहां रोड का भूमिपूजन किया। कुछ ग्रामीणों के कहना था कि रोड से पहले नाली बनाओ। जबकि रोड के साथ नाली बनेंगी ही।

बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह से जुड़ी सेवाएं देने वालों से अपील

हरदा। जिला प्रशासन हरदा द्वारा आगामी 20 अप्रैल को ''अक्षय तृतीया'' के अवसर पर बड़ी संख्या में होने वाले विवाह समारोहों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से विवाह से संबंधित सभी सेवा प्रदाताओं से विशेष अपील की गई है। जिला हरदा के विवाह से जुड़ी सभी सेवाएं देने वाले पंडित, धर्मगुरु, होटल, केटरर, टेंट हाउस संचालक, बैंड-बाजा वाले, ब्युटी पार्लर, घोड़ी-बग्गी संचालक, मैरिज गार्डन मालिक, छायाकार, स्टूडियो संचालक एवं अन्य आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि वे विवाह से पूर्व बालक-बालिका की आयु का सत्यापन अवश्य करें।

प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अनुराग दुबे ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे विवाह न केवल कानूनन वर्जित हैं, बल्कि बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। उन्होने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने में प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल ने मनाया स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस, सेवा कार्यों की दी जानकारी

भोपाल। रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य एवं गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों एवं उनके परिवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही, जिससे पूरा वातावरण आत्मीयता, फेलोशिप और आनंद से भर गया।

वर्तमान वर्ष की अध्यक्ष रोटेरियन बिशाल धूपे एवं सचिव रोटेरियन मृदुल प्रसाद ने क्लब की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आने वाले वर्षों में सेवा कार्यों को और सशक्त करने का संकल्प व्यक्त किया।

कार्यक्रम में क्लब के दो संस्थापक सदस्यों रोटेरियन के. जी. बंसल एवं रोटेरियन सुनील खखवा का विशेष सम्मान किया गया। साथ ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अमूल्य योगदान को याद किया गया। पिछले कुछ वर्षों में क्लब द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की भी सराहना की गई। क्लब द्वारा किए गए प्रमुख सेवा कार्यों में 175 से अधिक दिव्यांगों को निःशुल्क भोजन, 300 से अधिक व्हीलचेयर का वितरण, ग्रामीण विद्यालयों के छात्रों को 100 साइकिलें प्रदान करना, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए 17 लाख रुपये से अधिक के फिजियोथेरेपी उपकरण उपलब्ध कराना तथा शासकीय विद्यालय में कक्षा कक्ष निर्माण एवं फर्नीचर वितरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 'उड़ान' संस्था के माध्यम से छात्रों के लिए शैक्षणिक अभियान और सीहोर-आष्टा मार्ग पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं हेतु रोजगारमूलक प्रशिक्षण केंद्र का संचालन भी किया जा रहा है। रोटरी क्लब ईस्ट भोपाल, भोपाल का दूसरा सबसे पुराना एवं प्रतिष्ठित क्लब है, जो सेवा, फेलोशिप और नेतृत्व के मूल्यों पर निरंतर कार्य कर रहा है। क्लब के रोटेरियन अरुण दत्ता वर्ष 3040 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचे हैं।

कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने गीत-संगीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से पुरानी यादों को ताजा किया और आपसी फेलोशिप को मजबूत किया। अंत में रोटेरियन जी. के. छिब्बर ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन किया।

नर्मदापुरम में खेल मंत्री ने मल्टीस्पोर्ट्स टर्फ का किया शुभारंभ

विश्वास सारंग बोले- फिट युवा ही बना सकता है देश को मजबूत

नर्मदापुरम,(निप्र)। मप्र के सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास सारंग रविवार रात को अल्प प्रवास पर नर्मदापुरम पहुंचे। खेल मंत्री ने दादा कुटी पहुंचकर वहां पूजन की। फिर उन्होंने एक अत्याधुनिक खेल परिसर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में खेल मंत्री सारंग ने हर व्यक्ति के लिए खेल के महत्व को बताया।

उन्होंने कहा मैंने एक किताब में पढ़ा था कि शिकागो सम्मेलन से लौटकर आने के बाद विवेकानंद जी के पास कुछ युवा पहुंचे और बोले कि हम चाहते है कि आपके जैसे मार्ग पर चले, भगवा पहन संन्यास लेना चाहते है। सनातन का परचम लहराकर देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएं। विवेकानंद मुस्कुराएं बोले कि भारत देश को बड़ा बनाना चाहते हो तो उसके लिए भगवा धारण, संन्यास लेने की जरूरत नहीं, वो सामने फुटबॉल का मैदान पड़ा है। वहां जाओ, खेलों, अपने शरीर, मन, मस्तिष्क को ठीक करो। इस देश का नागरिक, युवा शारीरिक, मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा, तभी यह भारत बड़ा देश बनेगा।

खेल मंत्री ने कहा खेल किसी व्यक्ति को समाज के सुव्यवस्थित नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया है। हर एक व्यक्ति, समाज का हर एक अंग खेल से जुड़े। हिंदुस्तान को हिट करना है तो फिट करना होगा। फिटनेस के दौर में आज हम सभी तेज गति से आगे बढ़े। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। खेल मंत्री ने लोकार्पण के साथ ही बैटिंग भी की। इस दौरान सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक विजयपाल सिंह, आचार्य पंडित सोमेश परसाई, आध्यात्मिक गुरु सांई बल्लभदास, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीति शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, पूर्व विधायक सविता दीवान, जनपद अध्यक्ष, भूपेन्द्र चौंकाने सहित अन्य उपस्थित रहे।

नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने किया पदभार ग्रहण

बैतूल,(निप्र)। नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद, एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को बैतूल जिले के कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। उक्त आदेश के पालन में उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया।

जिले में आगमन पर नवागत कलेक्टर डॉ. सोनवणे का अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य अधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया गया। डॉ. सोनवणे इससे पूर्व आयुक्त नगर निगम रीवा सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

रोस्टर निर्धारित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की होगी नियमित समीक्षा : नवागत कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे से आज कलेक्ट्रेट में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए विभागीय प्रशासनिक संरचना, प्रगतिरत एवं स्वीकृत निर्माण कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभागवार रोस्टर निर्धारित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी। साथ ही, उन्होंने कलेक्टर कार्यालय भवन का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

टोल बचाने रॉन्ग साइड दौड़ रहे ट्रक-डंपर :नर्मदा पुल के पास अचानक कट मारने से हादसे का खतरा

नर्मदापुरम,(निप्र)। औबेदुल्लागंज-बैतूल हाईवे स्थित नर्मदा पुल के पास ट्रक, डंपर चालक 'शॉर्टकट' रास्ता अपना रहे हैं। हाईवे पर अचानक रॉन्ग साइड (नियम विरुद्ध) तरह से गाड़ी निकालने से खुद के साथ लोगों की जान खतरे में डाल रहे। ड्राइवर बुधवाडा टोल प्लाजा पर टोल बचाने के लिए यह शॉर्ट कट रास्ता अपना रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। रॉन्ग साइड से डंपर पार कराने से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही आम जनता की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है।

नर्मदापुरम से भोपाल जाते समय नर्मदा नदी के पुल से डेढ़ किमी दूर टोल बूथ है। टोल बूथ पर होने के बाद ही भोपाल से बैतूल जाने वाली सड़क पर आया जा सकता है। टोल पार करने से ड्राइवरों को टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए ड्राइवर नियम विरुद्ध तरह से सड़क पार कर रहे हैं। अचानक इस तरह सड़क पार करने से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए दुर्घटना का जोखिम बना रहता है।

कलेक्टर ने खेतों में पहुंचकर किया गेहूँ की वास्तविक उपज का निरीक्षण

हरदा,(निप्र)। जिले में किसानों को गेहूं उपार्जन हेतु पंजीयन स्लॉट बुक करने में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने ग्राम स्तर पर पहुंचकर किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। उन्होने ग्राम अहलवाडा में जाकर किसानों से सीधे संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को समझा। इस दौरान उन्होंने खेतों में खड़ी एवं कटाई उपरांत रखी गई गेहूं की फसल का अवलोकन कर वास्तविक उपज का आकलन किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को स्लॉट बुकिंग में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होने स्पष्ट किया कि शासन किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

केवल उत्पादन करना काफी नहीं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी : मंत्री पटेल

रायसेन,(निप्र)। रायसेन स्थित दशहरा मैदान में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन उन्नत कृषि विषय पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इसी क्रम में सेमीनार हॉल-1 में एफपीओ मीट का आयोजन किया गया, जिसमें केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृषि मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा सहित विधायकगणों, वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों द्वारा सहभागिता की गई।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि केवल उत्पादन करना ही काफी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उसकी प्रोसेसिंग भी जरूरी है। एफपीओ कृषक उत्पादक संगठन की स्थापना छोटे-छोटे किसानों को एक मंच पर लाकर उनकी आय बढ़ाना और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उद्देश्य के साथ की गई। इसकी

आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि पहले किसानों को जो बीज मिलता था, वह कई बार ऊगता ही नहीं था। इसी प्रकार किसी दवाई या कीटनाशक के उपयोग से फसल को ही नुकसान होने या नकली खाद देने की स्थिति में संबंधित पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी। बिचौलिए भी किसानों की मेहनत की उपज का सही दाम नही देते थे और स्वयं कई गुना लाभ कमाते है। इन कठिनाईयों से किसानों को बचाने के लिए एफपीओ की स्थापना की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों के बीच भरोसा बढ़ाने और उत्पाद की गारंटी के लिए एफपीओ की स्थापना की गई, जिसमें किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान कर बिचौलियों की श्रृंखला को समाप्त करने पर काम किया गया ताकि फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों को मिल सके। इसके अलावा छोटे किसान जो व्यक्तिगत रूप से बीज, खाद या मशीनरी महंगे में खरीदते हैं, उन्हें एफपीओ के माध्यम से थोक दर पर इनपुट (बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड) कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी प्रकार किसानों को उत्पाद की मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग की सुविधा मिली है जिससे कि वह केवल कच्चा माल नहीं बेचते बल्कि वैल्यू एडिशन (मूल्य संवर्धन) के द्वारा अधिक लाभ कमाते हैं। इसके अलावा एफपीओ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी करता है। इस दौरान एफपीओ से जुड़े किसानों द्वारा भी अपने अनुभव साझा किए गए।

वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को होगा

हरदा,(निप्र)। नालसा, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में लंबित प्रकरणों तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु 9 मई, 2026 को वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय, हरदा तथा तहसील न्यायालय, टिमरनी और खिरकिया में किया जावेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा, श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत बिल, जलकर, सम्पत्तिकर बिल संबंधी प्रकरण सेवा मामलें, जो सेवा निवृत्ति लाभों से संबंधित है, राजस्व तथा अन्य सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, प्री-लिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उन्होंने आमजन से नेशनल लोक अदालत में दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर राजीनामा योग्य प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करने की अपील की।

सोना 9 साल से अक्षय तृतीया पर दे रहा सॉलिड रिटर्न

नई दिल्ली, एजेंसी। सल्फर सोने की कीमतों में इस साल काफी उतार-चढ़ाव के देखते हुए इस बार

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना क्या मुनाफे का सौदा साबित होगा बता दें पिछली अक्षय तृतीया (अप्रैल 2025) के बाद से भारतीय स्पॉट मार्केट में सोने की कीमतों में 60 प्रतिशत का उछाल आया है, जिससे निवेशकों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। यह लगातार नौवां साल है, जब सोने ने निवेशकों को ठोस रिटर्न दिया है। भारत में सोना खरीदना सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और शुभ संकेत भी है। कुछ खास त्योहारों, जैसे धनतेरस, दिवाली और अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे समृद्धि, सौभाग्य और स्थायी धन की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया भी ऐसा ही एक पर्व है, इस बार 19 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है। ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार, यह त्योहार भारतीयों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है। इस साल जनवरी में सोना 1,80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। उसके बाद कीमतों में गिरावट आई है और अब यह करीब 1,50,000 रुपये के स्तर पर है। यह हालिया हाई से लगभग 30,000 रुपये सस्ता है। तेजी के बाद मुनाफावसूली और बढ़ती क्रूड कीमतों के कारण महंगाई की चिंताओं के चलते निवेशकों ने खूब मुनाफा कमाया। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा कीमतें निवेश के लिए एक अच्छा अवसर है। चॉइस ब्रोकिंग की कमोडिटी एक्सपर्ट कावेरी मोरे के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया से पहले भारत में मांग मजबूत बनी हुई है, हालांकि ऊंची कीमतों ने आम ग्राहकों की भारी खरीदारी को सीमित कर दिया है। वहीं, एक मुंबई-बेस्ड बुलियन डीलर का कहना है कि इस बार सोने-चांदी की खरीदारी भी बहुत कम है। माहौल ऐसा नहीं लग रहा कि त्योहार नजदीक आ रहा हो। ग्लोबल लेवल पर चीन में सोने की मांग कमजोर पड़ी है, लेकिन वहां का केंद्रीय बैंक लगातार 17वें महीने सोना खरीद रहा है, जो बुलियन में लगातार भरोसा दिखाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोने की कीमतों की रफ्तार धीमी जरूर होगी, लेकिन मौजूदा रुझान जारी रह सकता है। केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और जियो-पॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए सोना एक फायदे का निवेश बना हुआ है। बिजनेस हेड हर्षल दासानी कहते हैं, 'मौजूदा कीमतों पर सोने को रिटर्न के दौड़ वाला निवेश न समझें, बल्कि इसे अपने पोर्टफोलियो को स्थिर करने वाला साधन मानें।' हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पिछले साल जैसा तगड़ा रिटर्न दोहराना मुश्किल हो सकता है।

वर्ल्ड बैंक चीफ अजय बंगा ने किया आगाह, नजरअंदाज न करें

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने पॉलिसी बनाने वालों से बड़ी अपील की है। उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में जारी झगड़े के बीच पॉलिसीमेकर्स एक कहीं ज्यादा जरूरी लंबे समय की चुनौती को नजरअंदाज न करें। वह चुनौती है रोजगार पैदा करना। बंगा ने एक बड़ी असमानता की ओर ध्यान दिलाया। विकासशील देशों में अगले 10-15 सालों में लगभग 1.2 अरब लोग काम करने वाली आबादी में शामिल होंगे। लेकिन, मौजूदा अनुमानों के मुताबिक, सिर्फ 40 करोड़ रोजगार ही पैदा होंगे। इससे 80 करोड़ रोजगारों की भारी कमी रह जाएगी। यह एक ऐसा फासला है जिसके गहरे सामाजिक-आर्थिक नतीजे हो सकते हैं। बंगा ने माना कि बार-बार आने वाले वैश्विक झटकों के दौर में लंबे समय से चली आ रही ढांचागत समस्याओं पर ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता है। इन झटकों में कोरोना महामारी से लेकर मौजूदा भू-राजनीतिक तनाव तक शामिल हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक इंटरव्यू में बंगा ने कहा, 'हमें एक ही समय में दो काम करने होंगे। चलते भी रहना है और च्यूइंग गम भी चबाते रहना है।

तीन कंपनियों ने बनाया है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसे दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। पीएम मोदी के उद्घाटन के साथ ही 213 किलोमीटर लंबा छह लेन वाला यह एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी करीब ढाई घंटे में पूरी होगी। अभी देहरादून पहुंचने में करीब 6 घंटे लगते हैं।

इस एक्सप्रेसवे को तीन कंपनियों ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में 12000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है। यह कॉरिडोर पर्यटन और आर्थिक रूप से व्यापार और विकास के नए रास्ते खोलेगा। इस एक्सप्रेसवे के खुलने से न केवल दिल्ली-उत्तराखंड के बीच पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी।

तीन कंपनियों ने बनाया है दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसव के प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की है। इस एक्सप्रेसवे को तीन

कंपनियों ने मिलकर बनाया है। ये इस प्रकार हैं: इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम चार चरणों में पूरा हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यह एक्सप्रेसवे इन चरणों में पूरा हुआ है।

पहला चरण दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से शुरू हुआ था। करीब 32 किमी लंबे पहले फेज पर काम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नजदीक खेकड़ा (बागपत) तक चला।

दूसरे चरण का काम खेकड़ा (बागपत) से शुरू हुआ। करीब 120 किमी लंबा यह फेज सहारनपुर बायपास तक है। इस फेज को ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया गया। तीसरा फेज सहारनपुर बाईपास से उत्तराखंड में गणेशपुर तक रहा। यह फेज 42 किमी लंबा है। यह फेज गणेशपुर से देहरादून तक का है जो करीब 20 किमी लंबा है। इसमें 4.6 किमी का अपग्रेडेड हिस्सा शामिल है। बाकी हिस्सा नए सिरे से बनाया गया है। यह कॉरिडोर उत्तराखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इस आर्थिक गलियारे से प्रदेश में रोजगार, पर्यटन और व्यापार को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को पूरा होने में 6 साल से ज्यादा का समय लगा है। हालांकि कंस्ट्रक्शन का काम करीब 5 साल में ही पूरा हो गया। बाकी समय जमीन अधिग्रहण और केंद्र सरकार से फंड मिलने में लगा। इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इस प्रकार है:

फरवरी 2020 : केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।

जनवरी 2021 : अक्षरधाम से बागपत जिला सीमा तक के पहले दो चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण और निविदा आवंटन का काम पूरा हुआ।

नवंबर 2021 : हरिद्वार को इस एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 2,095 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

दिसंबर 2021 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को औपचारिक रूप से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण की आधारशिला रखी।

जनवरी 2022 : शामली-अंबाला एक्सप्रेसवे लिंक के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई।

विजय केडिया का फिर प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स पर दांव, खरीदे हैं 10 लाख शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने स्मॉलकैप कंपनी प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स पर फिर दांव लगाया है। केडिया ने प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के 10 लाख शेयर खरीदे हैं। प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयर सोमवार को बीएसई में उछाल के साथ 145.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच दिन में कंपनी के शेयरों में करीब 18 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। इस साल 30 मार्च के बाद से कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 263.30 रुपये है। वहीं, प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 104.05 रुपये है। शेयर मार्केट के दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स पर फिर दांव लगाया है। विजय केडिया ने कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.05 पर्सेंट हो गई है। विजय केडिया ने प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स में यह हिस्सेदारी 14.1 करोड़ रुपये में खरीदी है। इससे पहले, सितंबर 2025 तिमाही में भी केडिया के पास प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के 10 लाख शेयर थे। हालांकि, दिसंबर 2025 तिमाही में केडिया का नाम कंपनी के इनवेस्टर लिस्ट से बाहर था। प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स का मार्केट कैप सोमवार 13 अप्रैल 2026 को 1379 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। स्मॉलकैप कंपनी प्रिसिजन कैमशाफ्ट्स के शेयर पिछले 5 साल में 222 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

दनादन 11 बार बोनस शेयर बांट चुकी है मल्टीबैगर कंपनी, हर बार 2 शेयर पर दिए हैं 1 बोनस शेयर

नई दिल्ली, एजेंसी। मल्टीबैगर कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने अपने शेयरधारकों को दनादन बोनस शेयर बांटे हैं। संवर्धन मदरसन अपने निवेशकों को 11 बार बोनस शेयर का तोहफा दे चुकी है। कंपनी के शेयर सोमवार को बीएसई में 119 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी

के शेयरों में करीब 12 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में संवर्धन मदरसन के शेयर 40 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 136.10 रुपये है। वहीं, संवर्धन मदरसन के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 77.07 रुपये है। संवर्धन मदरसन, ऑटो कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स इंडस्ट्री से जुड़ी है। मल्टीबैगर कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने साल 1997 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 11 बार बोनस शेयर दिए हैं। संवर्धन मदरसन ने अपना पिछला बोनस शेयर जुलाई 2025 में दिया है। कंपनी ने साल 1997 से लेकर अब तक हर बार 1:2 के रेशियो में ही बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर बार प्रत्येक 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने नवंबर 1997, जुलाई 2000, जनवरी 2005, मई 2007, अगस्त 2012, नवंबर 2013, जून 2015, मई 2017, सितंबर 2018, अगस्त 2022 और मई 2025 में बोनस शेयर दिए हैं।

1997 में 100 शेयर खरीदने वाले निवेशक के पास अब होते 8600 से ज्यादा शेयर : अगर किसी निवेशक ने साल 1997 में बोनस शेयर दिए जाने से पहले संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के 100 शेयर खरीदे होते और अपने निवेश को बनाए रखा होता तो मौजूदा समय में उस व्यक्ति के पास इस मल्टीबैगर कंपनी के करीब 8614 शेयर होते। यह बात की एक रिपोर्ट में कही गई है। अगर साल 2000 से कैलकुलेशन करें संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल ने अपने निवेशकों को 10 बार बोनस शेयर बांटे हैं।

2 बार अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है कंपनी : संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल दो बार अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी ने अक्टूबर 2002 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा, तब कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा। इसके बाद मार्च 2004 में कंपनी ने अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 5 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा।

एलजी के शेयर बुधवार को मचाएंगे हलचल

लॉक-इन पीरियड खत्म होने से 44 करोड़ शेयर होंगे मुक्त

नई दिल्ली, एजेंसी। छुट्टी के बाद स्टॉक मार्केट खुलेगा तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर हलचल मचा सकते हैं। इसकी वजह है कंपनी के शेयरहोल्डर्स के लिए लागू लॉक-इन पीरियड का खत्म होना। इस लॉक-इन पीरियड के खत्म होते ही बड़ी संख्या में शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। नुवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्र इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों पर लगा छह महीने का लॉक-इन पीरियड अब समाप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन शेयरों को बेचा नहीं जा सकता था, वे अब बाजार में बेचने के लिए योग्य हो जाएंगे।हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि सभी शेयर एक साथ बिक जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब ये शेयर ट्रेडिंग के लिए खुले हैं।

नुवामा की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 65 प्रतिशत यानी करीब 44.12 करोड़ शेयर अब बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। मौजूदा कीमत के हिसाब से इन शेयरों की कुल वैल्यू लगभग 66,180 करोड़ बैठती है। दिसंबर 2025 तिमाही के अंत तक, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 85 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जो कि न्यूनतम 75 प्रतिशत की तय सीमा से ज्यादा है। पब्लिक शेयरहोल्डर्स की बात करें तो भारत के म्यूचुअल फंड्स के पास करीब 5.4 प्रतिशत होल्डिंग्स है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास करीब 3 प्रतिशत हिस्सेदारी है। करीब 10.6 लाख छोटे रिटेल निवेशकों, जिनका निवेश 2 लाख तक है, के पास कंपनी में 3.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

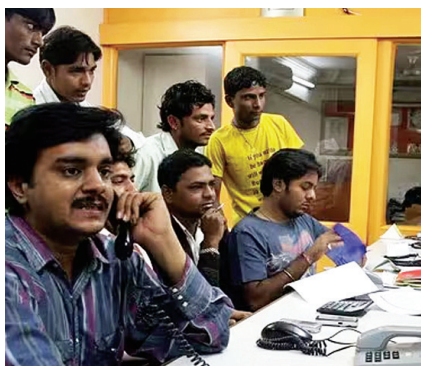

हालांकि, मार्च तिमाही के लिए कंपनी ने अभी तक नया शेयरहोल्डिंग डेटा जारी नहीं किया है।

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का शेयर प्राइस ट्रेंड: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयर सोमवार को 1.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,503.5 पर बंद हुए। हालांकि, यह अपने लिस्टिंग के बाद के हाई 1,749 से करीब 14 प्रतिशत नीचे है, लेकिन अभी भी अपने इश्यू प्राइस से ऊपर बना हुआ है। पिछले पांच सेशन में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है।

सब्जियों की कीमतों ने बढ़ाया किचन का बजट

नई दिल्ली, एजेंसी। बीते महीने सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर 3.40 फीसदी दर्ज की गई, जो फरवरी में 3.21 फीसदी रही थी। सोना-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी समेत अन्य वस्तुओं की कीमतों मे भी दर्ज की गई बढ़ोतरी। मार्च में सोना-चांदी के आभूषण, नारियल, टमाटर और फूलगोभी जैसी वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई, जिससे खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे किचन का बजट बढ़ गया। सोमवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 3.40 फीसदी रही, जो फरवरी 2026 में 3.21 फीसदी थी। बीते महीने ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा महंगाई 3.63 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 3.11 फीसदी दर्ज की गई। स्टेटवाइज आंकड़ों में तेलंगाना में सबसे ज्यादा महंगाई दर्ज की गई, जहां यह 5.83 फीसदी रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 4.05 फीसदी महंगाई दर्ज की गई है। उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान का स्थान रहा है। औसत उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक यानी रसोई के बजट पर असर डालने वाल खाद्य महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो मार्च में 3.87 फीसदी दर्ज की गई है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में खाने-पीने की चीजें 3.96 और शहरों में 3.71 फीसदी रही है। जबकि इससे पहले फरवरी में सीएफपीआई 3.47 फीसदी रही थी।

दुबई के कदम से भारतीय एयरलाइंस की बढ़ी टेंशन, सरकार से जवाबी एक्शन की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान संकट के चलते दुबई ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने भारतीय एयरलाइंस की टेंशन बढ़ा दी। 31 मई तक उसने विदेशी एयरलाइंस के लिए अपने यहां पाबंदी लगाई है। इसके तहत दुबई ने अपने एयरपोर्ट्स पर रोज सिर्फ एक फ्लाइट की सीमा तय की है। इससे भारतीय एयरलाइंस के बीच रेवेन्यू के नुकसान की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने किसी भी दूसरे देश की एयरलाइंस के मुकाबले इस डेस्टिनेशन के लिए ज्यादा फ्लाइट्स की योजना बनाई थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने भारत सरकार से अपील की है कि वह दुबई के अधिकारियों पर इन पाबंदियों को हटाने का दबाव डाले। 31 मार्च को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, अगर ऐसा नहीं होता है तो एफआईए ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की एयरलाइंस जैसे बदले में वैसी ही पाबंदियां लगाने का सुझाव दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई एयरपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अप्रैल से 31 मई के बीच एयरलाइंस को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मख्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों के लिए रोजाना सिर्फ एक राउंड ट्रिप की अनुमति होगी। रिपोर्ट के अनुसार, 27 मार्च के एक निजी ईमेल में दुबई एयरपोर्ट ने एयरलाइंस को लिखा, 'एयरलाइंस के लिए रोजाना एक रोटेशन की सीमा जारी रहेगी।

बाजार की आंधी में 7 कंपनियों के शेयरों का दबदबा कायम

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले एक साल के दौरान घरेलू शेयर बाजारों में काफी उठा-पटक देखने को मिली है। लेकिन इस दौरान कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिया है। निफ्टी500 स्टॉक में से 7 कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयरों की कीमतों में 150 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। मार्केट की मौजूदा परिस्थितियों का इन कंपनियों पर कोई असर नहीं दिखा है। बता दें, पिछले एक साल में निफ्टी50 में 4 प्रतिशत और निफ्टी500 में 7 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल में 207 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 2866 प्रतिशत और 5 साल में 3494 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई 1 अप्रैल को 4344 रुपये रहा है।

बीते एक साल में इस सरकारी कंपनी के शेयरों का भाव 192 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 431.50 रुपये और 52 वीक लो लेवल 144.71 रुपये है। पीएसयू स्टॉक में तीन साल में 425 प्रतिशत और 5 साल में 648 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

इस कंपनी की लिस्टिंग अगस्त 2025 में हुई थी। इश्यू प्राइस से अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 190 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 675 रुपये था। बता दें, 13 अप्रैल 2026 के शेयरों का भाव 1954.20 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।

एनएसई का 20000 करोड़ रूपये का आईपीओ जल्द आएगा

नई दिल्ली, एजेंसी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। एनएसई भी सेबी के पास अपने के ड्राफ्ट पेपर दाखिल करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इससे 20,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए जा सकते हैं। यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। सारा फंड मौजूदा शेयरधारकों को जाएगा। अगर आप अभी ह्स्श्व के अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं, तो आप इस में बेचने वालों में शामिल नहीं होंगे। केवल वही पुराने शेयरधारक बेच पाएंगे, जिनके पास जून 2025 से लगातार शेयर हैं।

खबरों के मुताबिक जून 2026 में सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर सकता है और इस साल के अंत तक आईपीओ के आने की उम्मीद है। सेबी के नियमों के अनुसार, केवल वही शेयरधारक में शेयर बेच पाएंगे, जिनके पास जून 2025 से लगातार पूरी तरह भुगतान वाले ह्स्श्व शेयर हैं। यह नियम उन लोगों को रोकता है, जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए आखिरी समय में अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदते हैं। इसका मतलब साफ है अगर आप अभी ह्स्श्व के अनलिस्टेड शेयर

खरीदते हैं, तो आप में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पात्र शेयरहोल्डर्स को भाग लेने के लिए 27 अप्रैल, 2026 तक अपनी 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' जमा करना होगा, जो शेयरधारक समय पर नहीं देंगे, वे में शेयर नहीं बेच पाएंगे।

सेबी का एक साल का नियमः सेबी के नियमों के तहत, मौजूदा शेयरधारक पेपर दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले से लगातार शेयर होल्ड कर रहे हों, तभी वे ह्स्श्व में बेच सकते हैं। इस सेकेंडरी सेल में अपनी लगभग 4.5 प्रतिशत इक्विटी बेचने की योजना बना रहा है। 30 जून, 2025 तक 1,59,394 शेयरहोल्डर्स थे। 31 मार्च, 2025 तक 39,201 शेयरहोल्डर्स और 31 दिसंबर, 2025 तक 1,86,481 शेयरहोल्डर्स थे।

आईपीओ के लिए किन-किन बैंकों को चुना गया

पिछले महीने ह्स्श्व ने इस के लिए 20 बैंकों को नियुक्त किया, जो एक रिकॉर्ड है। इससे पहले प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 18 बैंकों के साथ रिकॉर्ड बनाया था। 8 लॉ फर्मों को भी सलाहकार के तौर पर चुना है। फरवरी 2026 में ह्स्श्व ने एक समिति बनाई और स्वतंत्र सलाहकार नियुक्त किया, जो चयन प्रक्रिया की देखरेख करेगा।

एलपीजी और तेल ही नहीं, किसानों सामने भी खड़ी है बड़ी समस्या, सल्फर की वजह से बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली, एजेंसी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावित होने की वजह से सिर्फ तेल और एलपीजी ही नहीं सल्फर की समस्या खड़ी हो सकती है। सल्फर आज के समय में फर्टीलाइजर्स, बैटरी, केमिकल्स, मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूरी है। यूरिया से कंप्यूटर चिप्स तक के लिए सलफ्यूरिक एसिड काफी जरूरी है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बाधित होने की वजह से फैक्टरी प्रोडक्शन धीमा और फूड की कीमतें बढ़ सकती हैं। बता दें, भारत अपनी जरूरत का बढ़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से मंगाता है। ऐसे में सल्फर की आपूर्ति प्रभावित होने की वजह से खाद की कीमतों पर असर दिखेगा। इससे किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो सकती है।

सल्फर क्यों है इतना जरूरी: खाड़ी के देशों से दुनिया के एक्सपोर्ट का 45 प्रतिशत उत्पादन होता है। तेल और गैस रिफाइनिंग का सल्फर एक बायप्रोडक्ट है। ऐसे में तेल की आपूर्ति प्रभावित होने का सीधा

असर सल्फर पर पड़ता है। बता दें, दुनिया का 60 प्रतिशत सल्फर डिमांड सिर्फ फर्टीलाइजर्स के लिए आता है। बाकि बचा 40 प्रतिशत केमिकल्स, मेटल प्रोसेसिंग, बैटरी और चिप फाइब्रेकेशन के लिए होता है।

भारत के लिए क्यों है चिंता की बात: यूरिया और फॉस्फेट फर्टीलाइजर्स के लिए सल्फर बहुत जरूरी है। सल्फर की आपूर्ति प्रभावित होने की स्थिति में सरकार पर खाद की सब्सिडी बढ़ाने का दबाव होगा। वहीं, किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ सकता है। खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केमिकल और मेटल का प्रोडक्शन करने वाले लोगों की लागत बढ़ने का दबाव रहेगा।

चीन ने भी दिखाई सख्ती: मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए चीन ने मई से सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट को रोकने का संकेत दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह 2026 सख्ती 2026 तक लगाई जा सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन में सल्फर की कीमतों में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने आने वाले खरीफ फसल के लिए न्यूट्रियन्ट आधारित सब्सिडी में करीब 12 प्रतिशत का इजाफा किया है। अगर युद्ध लम्बा खींचा तब की स्थिति में सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में सरकार के पास तब दो ही विकल्प रह जाएंगे। पहला विकल्प कीमतों को किसानों तक बढ़ा दिया जाए।

प्रफुल्ल हिंगे ने आईपीएल में रचा इतिहास

- शोएब अख्तर समेत 8 खिलाड़ियों की बराबरी की

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के 21वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपनी प्लेइंग 11 में प्रफुल्ल हिंगे को शामिल किया। प्रफुल्ल ने अपने डेब्यू मैच में ही फिर वो कमाल कर दिया और आईपीएल इतिहास में किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया था। यही नहीं प्रफुल्ल ने शोएब अख्तर समेत 4 खिलाड़ियों की बराबरी भी कर ली।

प्रफुल्ल ने पहले ओवर में 3 विकेट लिए

प्रफुल्ल हिंगे ने राजस्थान के खिलाफ पारी के पहले ही ओवर में 3 विकेट झटके और आईपीएल इतिहास में बतौर डेब्यूटेंट पहले ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने। प्रफुल्ल ने वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस को आउट कर राजस्थान को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। ये तीनों बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल पाए। प्रफुल्ल की गेंदबाजी का इन सभी बल्लेबाजों को पास कोई जवाब नहीं था और सबने उनके सामने सरेंडर कर दिया। प्रफुल्ल ने इस लीग में 1191 मैचों के बाद पहले ओवर में 3 विकेट लेने का कमाल किया।

पहली पारी में 4 विकेट

2026	प्रफुल हिंगे
2025	अश्विनी कुमार
2019	अल्जारी जोसेफ
2017	एंड्रयू टे
2015	डेविड वाइज
2012	केवोन कूपर
2011	पॉल वाल्थाटी
2009	शादाब जकाती
2008	शोएब अख्तर

पिता करते थे मजदूरी, मां ने गहने बेच कर दिलाए थे जूते

- साकिब हुसैन आईपीएल में यादगार डेब्यू की दास्तां

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का 21वां मैच पूरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम रहा। इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने दोनों विभाग में लगातार चार मैच जीतकर आई राजस्थान रॉयल्स की टीम को पीट दिया। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सनराइजर्स के दो डेब्यूटेंट भारतीय तेज गेंदबाजों को। अभी तक इस सीजन बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी, मुकुल चौधरी, समीर रिजवी जैसे खिलाड़ियों ने कमाल किया था। अब गेंदबाजी में भी भारत का युवा टैलेंट सामने आ गया है। यह दो नाम हैं प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन के।

30 लाख में खरीदे साकिब

साकिब हुसैन का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ था। यह खिलाड़ी आईपीएल में नया नहीं है लेकिन बस खेलने पहली बार उतरा। इससे पहले 2024 में केकेआर के लिए इस खिलाड़ी को स्क्वाड में जगह मिली थी। मगर कोलकाता के लिए यह खिलाड़ी खेल नहीं पाया। उसके बाद आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख के बेस प्राइस पर 21 साल के पेसर को खरीदा। यह फैसला सही था, इसे साकिब ने अपने यादगार डेब्यू से साबित किया।

चेन्नई के मैचों का बदला कार्यक्रम

सीजन के बीच क्यों बदल दिए गए वेन्यू?

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के बीच सीजन ही चेन्नई सुपर किंग्स के दो मैचों का कार्यक्रम बदल गया है। आईपीएल द्वारा सोमवार 13 अप्रैल इसकी जानकारी देते हुए रिलीज जारी की गई है। इसके मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले दोनों मैचों के वेन्यू बदल दिए गए हैं। दरअसल दोनों टीमों के बीच होने वाले इस सीजन दोनों मैचों के वेन्यू में अदला-बदली हुई है।

कौन से दो मैचों का बदला कार्यक्रम?

26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाला दोपहर का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था। अब इस मैच का वेन्यू अहमदाबाद से बदलते हुए चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है। यह मुकाबला अब चेन्नई में दोपहर 3.30 बजे (IST) से खेला जाएगा। वहीं इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के दूसरे मुकाबले में भी बदलाव हुआ है। यह मैच 21 मई 2026 को होना है और यह शाम 7.30 बजे से शुरू होगा।

वैभव दे सकते है टीम इंडिया में दस्तक

बनेंगे भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी

आयरलैंड टी- 20 दौरे के लिए चयन लगभग तय

नई दिल्ली। जून 2026 में भारत के आयरलैंड दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी के चुने जाने की संभावना है। यदि वह चुने गए तो देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनेंगे। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार, चयनकर्ता 15 साल के इस खिलाड़ी को इंग्लैंड के व्हाइट-बॉल दौरे से ठीक पहले होने वाली इस छोटी T20I सीरीज में बड़ा मौका दे सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्र ने इसकी पुष्टि की। सूत्र ने बताया, ''वह आयरलैंड दौरे के लिए दावेदारों में शामिल है और चयनकर्ताओं ने कई अन्य खिलाड़ियों के साथ उसका नाम भी शॉर्टलिस्ट किया है।''

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पिछले सीजन दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों की जमकर धुनाई की थी। इस साल भी वह उसी लय में खेल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 26 गेंदों में 78 रन, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन और मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंदों में 39 रन बनाए हैं। वह बड़े नामों से बिल्कुल भी घबराते हुए नहीं दिखते। उन्होंने जसप्रीत बुमराह (जिन्हें पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा था) और जोश हेज़लवुड जैसे गेंदबाजों का भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना किया।

जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी चुने जा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी

राष्ट्रीय चयनकर्ता इस युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल करने के लिए ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन संभावना है कि वे उसे थोड़ी कमजोर टीम के खिलाफ खेलने का मौका देंगे। अगर वैभव सूर्यवंशी का शानदार रन बनाने का सिलसिला जारी रहता है तो चयन समिति उसे आयरलैंड में होने वाली आगामी सीरीज के साथ-साथ इस साल के अंत में होने वाले जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी चुनेगी। यहां तक कि भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी राष्ट्रीय चयनकर्ताओं से कहा है कि वे देर न करें और वैभव सूर्यवंशी को तुरंत टीम में चुन लें। सचिन तेंदुलकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू 16 साल और 205 दिन की उम्र में किया था।

वैभव तोड़ सकते हैं शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड

पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों की बात करें तो शेफाली वर्मा भारत के लिए खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। शेफाली ने 15 साल, सात महीने और 27 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अगर वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड दौरे पर खेलते हैं तो वह शेफाली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारत बनाम आयरलैंड टी20 इंटरनेशल सीरीज के दो मैच 26 और 28 जून 2026 को होने हैं। पता चला है कि IPL 2026 के खत्म होने के एक महीने से भी कम समय के भीतर होने वाली इस सीरीज के लिए दूसरी श्रेणी की टीम चुनी जाएगी। चयन समिति वैभव सूर्यवंशी और हाल के समय में अपनी छाप छोड़ने वाले अन्य खिलाड़ियों को इस सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव देने के लिए उत्सुक है। आयरलैंड सीरीज के बाद इंग्लैंड का दौरा होगा। एक जुलाई से शुरू होने वाले इंग्लैंड दौरे पर भारत पांच T20 और तीन ODI मैच खेलेगा। इन दोनों सीरीज में कई वरिष्ठ खिलाड़ियों के लौटने की उम्मीद है। बल्लेबाजी के

अपने तरीके के बारे में बताते हुए वैभव सूर्यवंशी कह चुके हैं कि वह कभी भी अपने सामने गेंदबाज के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उस गेंद के बारे में सोचते हैं जो उनकी तरफ आ रही होती है।

सचिन का रिकॉर्ड क्लासेन ने तोड़ा

आईपीएल में पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बैटर

हैदराबाद। हैदराबाद के बैटर हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 के 21वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए, लेकिन अपनी टीम के लिए 26 गेंदों पर 40 रन की अहम पारी खेली और इस दौरान 3 छक्के व एक चौका भी लगाया। क्लासेन ने अपनी इस पारी के दम पर सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया।

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड- क्लासेन ने राजस्थान के खिलाफ 40 रन की पारी खेली और आईपीएल की पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो छठे नंबर पर आ गए। क्लासेन ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा जो 1683 रन के साथ पहले छठे नंबर पर थे, लेकिन अब वो 7वें नंबर पर आ गए। इस लीग में पहले 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 2236 रन बनाए थे जबकि दूसरे नंबर पर शॉन मार्श 1933 रन के साथ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर माइक हसी हैं जिन्होंने 1777 रन बनाए थे जबकि चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ 1771 रन बनाए हैं।

पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बैटर

- 2236 रन : क्रिस गेल
- 1933 रन : शॉन मार्श
- 1777 रन : माइक हसी
- 1771 रन : ऋतुराज गायकवाड़
- 1725 रन : शेन वॉटसन
- 1704 रन : हेनरिक क्लासेन
- 1683 रन : सचिन तेंदुलकर

8 चौके, 6 छक्के

इशान किशन ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से ठोके 91 रन

फिर भी बनाया अनचाहा रिकॉर्ड

नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान इशान किशन ने आईपीएल 2026 के 21वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की और 44 गेंद पर 91 रन ठोके। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और छह छक्के लगाए और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन ठोके, लेकिन इस मैच में वह शतक से चूक गए। इशान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 9 रन पीछे रह गए अपने शतक से। उन्होंने इस बेहतरीन पारी के बावजूद हैदराबाद के लिए एक अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में एंट्री कर ली है। इशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 90s में आउट होने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले इस लिस्ट में तीन बार डेविड वॉर्नर और एक बार जॉनी बेयरस्टो का नाम दर्ज है।

आईपीएल 2026 में 20 में से 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर

पावरप्ले में रन वर्षा, पांच बार 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में 20 मैच हो गए हैं और आंकड़े बताते हैं कि यह अबतक का सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी वाला सीजन रहा है। 200 का आंकड़ा आम हो गया है। 20 मैच में 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। इतनी आसानी से 200 रन बनने का कारण ज्यादा छक्के लगने है। आईपीएल 2026 में छक्के लगने की दर 12.24 है। यानी लगभग हर 13 गेंद पर एक छक्का लग रहा है।

बल्लेबाज पावरप्ले का ज्यादा से ज्यादा से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि 5 बार बल्लेबाज अर्धशतक 20 से कम गेंद पर लगा चुके हैं। आईपीएल में पहली बार 20 मैचों के बाद रन रेट 10 रन प्रति ओवर तक पहुंच गया है। इससे पहले किसी सीजन में 20 मैच के बाद सबसे ज्यादा रन रेट 2025 में 9.52 था। रनरेट में इजाफे का कारण पावरप्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी हैं।

- **अंत के ओवरों में रनरेट गिरा-** मिडिल-ओवर का रन रेट भी बढ़ा है, लेकिन 14 प्रतिशत से थोड़ा कम। अंत के ओवरों में रनरेट गिरा है। यह 10 रन प्रति ओवर से थोड़ा ज्यादा है। पिछले चार सालों में डेथ ओवर और पावरप्ले के बीच रन रेट में अंतर कम से कम दो रन प्रति ओवर था। इस साल यह घटकर आधा रन प्रति ओवर रह गया है। 2022 में डेथ ओवर्स में रन रेट 11.57 था। 2026 में यह 10.44 है। 2024 में 11.54, 2023 में 11.2 और 2025 में 11.39 था।
- **200 से ज्यादा का स्कोर 5 बार हासिल-** बल्लेबाजों के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी आसानी से 200 से ज्यादा का लक्ष्य हासिल किया गया है। पिछले साल पहले 20 मैच में 11 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना था। इस बार 20 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना है। पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 18 पारी में 11 बार इसे हासिल किया है। इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों के लिए लक्ष्य तक पहुंचना काफी नॉर्मल हो गया है।

10 रन प्रति ओवर

आईपीएल इतिहास में पहली बार

आईपीएल 2026 में पहले 20 मैचों के बाद रन रेट 10.00 रन प्रति ओवर तक पहुंचा है। यह किसी भी सीजन में 20 मैच के बाद का अबतक का सर्वोच्च रन रेट है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2025 का था, जब रन रेट 9.52 था। पावरप्ले में विस्फोटक बल्लेबाजी इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है।

पांच बार 20 से कम गेंदों पर अर्धशतक- आईपीएल 2026 में बल्लेबाज काफी तेजी से अर्धशतक तक पहुंच रहे हैं। अबतक 48 पचासे लगे हैं। पांच अर्धशतक 20 से कम गेंदों पर लग गए हैं।

स्वामी प्रकाशक मुद्रक पंकज सिंह भदौरिया द्वारा श्री बालाली प्रिंटर्स प्लाट नंबर 137, 138, 139 सेक्टर 01 स्पेशल इंडस्ट्रीयल एरिया गोविन्दपुरा भोपाल, मप्र से मुद्रित कर 432 सेक्टर बी सर्वधर्म कालोनी, कोलार दामखेड़ा हुजूर भोपाल 462042 मप्र से प्रकाशित। संपादक- पंकज सिंह भदौरिया। (सभी विवाद भोपाल न्यायालय में मान्य होंगे।)

संक्षिप्त समाचार

थाने-थानेदार की रेटिंग अब जनता करेगी, हर थाने में लगा क्यूआर कोड

फरीदाबाद, एजेंसी। अब थाने और थानेदार की रेटिंग क्यूआर कोड से तय होगी। इसके

लिए सभी थाने और चौकियों में क्यूआर कोड लगाए गए है, जिनको स्कैन करके थाने में आने वाले शिकायतकर्ता को फीडबैक देना होगा। इसी के आधार पर तय होगा कि किस थाने में जनता के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, वहीं जिन थानों में लगे स्कैन पर पब्लिक के फीडबैक सही नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ खुद पुलिस आयुक्त की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सभी जिलों के पुलिस आयुक्त को आदेश दिए थे कि वह थाने और चौकी में शिकायतकर्ता के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करे। इसके साथ ही थाने में आने वाले व्यक्ति के बैठने और उसके पेयजल की व्यवस्था भी हो। जिले में कुल 29 थाने और 30 चौकी है। थानों में प्रतिदिन आठ से दस लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में कई बार पुलिस पर कई बार शिकायतकर्ता द्वारा यह भी शिकायत की जाती है कि उनकी सुनवाई नहीं की गई या उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। क्यूआर कोड पर आने वाली शिकायतों या किसी भी तरह के फीडबैक का प्रतिदिन रिव्यू किया जाएगा। फीडबैक के अनुसार थाने और चौकी में अगर किसी तरह की कमी होती है तो उसमें सुधार किया जाएगा। इसके साथ शिकायतकर्ता के साथ गलत व्यवहार करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक शिकायतकर्ता के पास फीडबैक देने को लेकर कोई सही मंच नहीं था। यह पूरी प्रक्रिया पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए है। थाने में आने वाले शिकायतकर्ता को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी अगर यहां पर सुनवाई सही तरीके से नहीं हुई तो वह अपनी आवाज दूसरी जगह नहीं उठा सकता है।

अब मृत वन्यजीव को जलाने की जगह किया जाएगा संरक्षित

गुरुग्राम, एजेंसी। साइबर सिटी में प्रदेश का पहला टैक्सिडर्मी सेंटर होगा। इसके लिए जिला अदालत के नजदीक वन विभाग कार्यालय के पीछे बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। अगले महीने से सेंटर चालू करने का प्रयास है। सेंटर चालू होने के बाद मृत वन्यजीवों को जलाया नहीं जाएगा बल्कि खाल सहित उसके सभी अंग सुरक्षित रखे जाएंगे। सेंटर में जिस वन्यजीव का खाल होगा उसके अनुरूप ढांचा तैयार किया गया। ढांचा तैयार होने के बाद उसमें खाल लगा दिया जाएगा, जिससे कि वह जीवित वन्यजीव की तरह दिखाई दे। ढांचों को वन्यजीव जागरूकता केंद्रों में लगाया जाएगा ताकि लोग वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सकें। प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में काफी संख्या में वन्यजीव हैं। उदाहरणस्वरूप अरावली पहाड़ी क्षेत्र में ही तेंदुआ, हिरण, गिदड़ सहित कई प्रकार के काफी संख्या में वन्यजीव हैं। वर्तमान में यदि किसी भी वन्यजीव की यदि मृत्यु प्राकृतिक तौर पर या हादसों में होती है तो पोस्टमार्टम करने के बाद उसे जला दिया जाता है क्योंकि टैक्सिडर्मी सेंटर की सुविधा नहीं है। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा। प्रदेश में कहीं भी वन्यजीव की मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम के बाद उसे साइबर सिटी के टैक्सिडर्मी सेंटर में लाया जाएगा। सेंटर में फ्रीजर की सुविधा होगी। फ्रीजर में कई दिनों तक बाडी रखी जा सकेगी। बता दें कि टैक्सिडर्मी सेंटर में जानवरों की खाल उतारकर पहले उसे कीटाणुरहित किया जाता है। फिर कृत्रिम शरीर पर लगाकर स्टफ किया जाता है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित जंगल सफारी पार्क में जागरूकता केंद्र भी बनाया जाएगा। उसमें प्रदेश के वन क्षेत्रों में रहने वाले वन्यजीवों के बारे में जानकारी दी जाएगी। टैक्सिडर्मी सेंटर में बनाए जाने वाले ढांचों को जागरूकता केंद्र में लगाया जाएगा।

श्रमिकों को मिलेगी कम से कम 20 हजार मजदूरी? योगी सरकार ने साफ की स्थिति

गिनाईं मजबूरियां, भ्रामक खबरों का खंडन और मजदूरी की सच्चाई

नोएडा, एजेंसी। नोएडा में श्रमिकों के उग्र आंदोलन और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही '20 हजार रुपये न्यूनतम वेतन' की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने 20,000 न्यूनतम मजदूरी की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही, सरकार ने वर्तमान मजदूरी की दरें जारी करते हुए यह भी बताया कि आखिर किन तकनीकी और कानूनी कारणों से अभी राष्ट्रीय स्तर का 'फ्लोर वेज' लागू नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर यह झूठ फैलाया जा रहा है कि सरकार ने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20,000 प्रति माह तय कर दिया है। सरकार ने साफ किया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11,313.65, अर्धकुशल के लिए 12,446 और कुशल श्रमिकों के लिए 13,940.37 अधिसूचित है। सरकार ने इसे गुमराह करने वाली साजिश करार दिया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम वेतन के निर्धारण में कई कानूनी प्रक्रियाएं बाधा बनी हुई हैं। केंद्र सरकार वर्तमान में नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर 'फ्लोर वेज' (न्यूनतम आधार रेखा) निर्धारित करने की प्रक्रिया में है। जब तक केंद्र सरकार इसे अंतिम रूप नहीं दे देती, तब तक राज्य अपने स्तर पर व्यापक

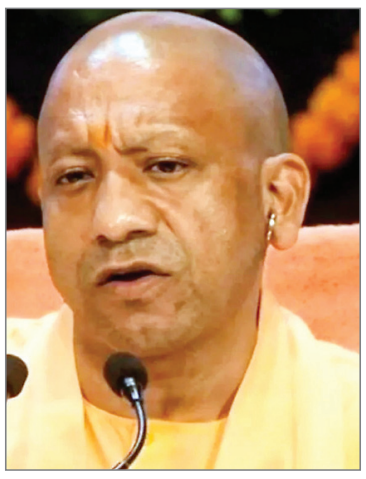

बदलाव नहीं कर पा रहे हैं।

बताया कि राज्य सरकार अभी नियोक्ता संगठनों और श्रमिक यूनियनों के साथ विचार-विमर्श के दौर में है। सभी पक्षों के सुझावों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि औद्योगिक विकास और श्रमिकों के हितों में संतुलन बना रहे।

सरकार ने बताया कि वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही भविष्य में न्यूनतम वेतन की स्थायी दरें तय की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया अगले माह से शुरू होने की संभावना है। सरकार ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में उद्योग जगत वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है और निर्यात में कमी आयी है। इसके साथ ही श्रमिकों द्वारा उठाई गई समस्याएं एवं उनकी मांगें भी प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं विचारणीय हैं। ऐसी परिस्थिति में दोनों उद्योग और श्रमिक के बीच सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया जाना जरूरी है।

हालांकि, नोएडा और गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में सोमवार को हुए बवाल को देखते हुए सरकार ने एक 'बीच का रास्ता' निकाला है। हाई पावर कमेटी की सिफारिश पर अंतरिम वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। इसके तहत नोएडा और गाजियाबाद के अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाकर ?13,690 कर दिया गया है। यह वृद्धि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि नया वेज बोर्ड अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे देता।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में कहा है कि आंदोलन की आड़ में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले 'बाहरी और अराजक तत्वों' को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, उन्होंने नियोक्ताओं को भी चेतावनी दी कि वे ओवरटाइम भुगतान और महिला सुरक्षा जैसे नियमों में कोताही न बरतें।

फरीदाबाद नागरिक अस्पताल में व्यवस्था गड़बड़

बीपीएल मरीजों को नहीं मिल रहा सीटी स्कैन-एमआरआई

फरीदाबाद, एजेंसी। जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट

पार्टनरशिप नीति(पीपीपी) के तहत चल रहे सेंटर में ओपीडी में आने वाले बीपीएल कार्डधारक मरीजों को सीटी स्कैन व एमआरआइ की सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पात्र होने के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निराश ही लौटना पड़ रहा है। या फिर निजी संस्थानों में टेस्ट कराने को मजबूर हैं। जबकि प्रदेश सरकार की ओरसे नागरिक अस्पताल में लगभग 10 वर्ष पहले पीपीपी के तहत सेंटर शुरू किया गया था,ताकि नागरिक अस्पताल में कम शुल्क पर आम मरीजों को यह सुविधा मिल सके और बीपीएल को निश्शुल्क मिले। हैरानी की बात है कि इस सुविधा का लाभ लेने को कई बिचौलिये भी सक्रिय हो गए और उन लोगों का टेस्ट कराने लगे, जो हकदार भी नहीं हैं। पहले अस्पताल प्रबंधन के सत्यापन के बाद ही बीपीएल कार्डधारक का टेस्ट हो पाता था। सत्यापन अब भी होगा, मगर डे केयर फाइल बनाई जाएगी। इस मामले में गड़बड़ीकी शिकायत के चलते ही अब स्वास्थ्य महानिदेशक डा. मनीष बंसल के आदेश पर ओपीडी के डाक्टर की सलाह पर बीपीएल कार्डधारक के टेस्ट नहीं हो रहे हैं। डीजी के आदेश अनुसार मरीज की डे केयर फाइल बनाई जानी अनिवार्य की गई है।

डॉक्टर सभी मरीजों की फाइल नहीं बना रहे हैं। बहुत से डॉक्टरों को डीजी के आदेश के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। ऐसे में कई बीपीएल कार्डधारकों को टेस्ट की सुविधा नहीं मिल पा रही है और वी निराश लौट रहे हैं। डीजी के आदेश से पहले ओपीडी पंजीकरण कार्ड पर ही सीटी स्कैन व एमआरआइ कर दिया जाता था। गौछी गांव निवासी मनीषा बीपीएल कार्डधारक हैं। उनकी बेटी नेहा के पेट में दर्द है। उल्टी भी हो रही है। नागरिक अस्पताल में आने पर डाक्टर ने पेट का सीटी स्कैन करवाले की सलाह दी तो वह सेंटर में आ गए। मनीषा ने बताया कि सेंटर में उनकी बेटी का सीटी स्कैन नहीं हो पाया।

आरएसएस प्रमुख बोले- संकट में दुनिया को राह दिखाता है भारत, संतों का ज्ञान दे रहा दिशा

नागपुर, एजेंसी। नागपुर में आयोजित ' श्री मज्जिनेंद्र पंचकल्याणेश्वर प्रतिष्ठा महोत्सव ' के दौरान भागवत ने कहा, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद की आंधियों ने दुनिया की कई सभ्यताओं को कमजोर कर दिया, लेकिन भारत अपनी मूल पहचान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। उनके अनुसार, यह स्थिरता भारत की आध्यात्मिक चेतना का परिणाम है। उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रीस, मिस्र और रोम जैसी सभ्यताएं इतिहास में विलीन हो गईं, जबकि भारत आज भी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ मौजूद है। इसका कारण संतों और ऋषियों द्वारा दी गई ज्ञान परंपरा है, जो समाज को निरंतर दिशा देती रही है।

भागवत ने समाज में संतों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके विचारों को जीवन में अपनाने से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे इस आध्यात्मिक धरोहर को समझें और अपने आचरण में उतारें। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक भारत अपनी मूल भावना के साथ कायम रहेगा, तब तक विश्व में संतुलन और शांति बनी रहेगी। भागवत ने कहा, समाज को आकार देने में संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदू समाज, हमारे राष्ट्र का समाज, धीरे-धीरे खुद को ढालने और रूपांतरित करने की अनूठी क्षमता रखता है। यह इसलिए है क्योंकि हमारे देश के संत, ऋषि और तपस्वी निरंतर हमारे समाज को आकार दे रहे हैं और तैयार कर रहे हैं। बाहरी दुनिया भौतिकवाद, संकीर्णतावाद और उपभोक्तावाद के तूफान से घिरी हुई है, ये वे शक्तियां हैं जिन्होंने अन्य समाजों के विघटन का कारण बनी हैं। फिर भी, हमारे लिए, वह लहर बस हम पर से गुजर जाती है। हम अपने मूल स्वरूप में अडिग और अपरिवर्तित रहते हैं। यह लचीलापन आध्यात्मिक ज्ञान का फल है। यह हमारे संतों द्वारा हम पर प्रदत्त कृपा है।

मोदी और ममता बनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं: ओवैसी

40 हजार मुसलमानों को दिए नोटिस- ओवैसी

कोलकाता, एजेंसी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। मुर्शिदाबाद जिले की रघुनाथगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, 'जब एक वीडियो सामने आया तो मैंने घोषणा की कि मजलिस बंगाल के मुसलमानों के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। बताइए कि क्या ममता बनर्जी ने भाजपा का साथ नहीं दिया? पीएम मोदी और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पीएम मोदी और ममता भाई-बहन जैसे हैं। ममता ने दावा किया था कि वे बंगाल में वक्फ एक्ट लागू नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके वोट हासिल करने के लिए झूठ बोला।'

यह आरोप तब आया जब टीएमसी ने एक्स पर एक स्टिंग वीडियो पोस्ट किया, जिसमें छक्कप्रमुख हुमायूं कबीर 1000 करोड़ रुपये के सौदे की बात करते दिख रहे हैं। एआईएमआईएम ने कहा कि इससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए दावा किया कि समुदाय के साथ गंभीर अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा, 'बंगाल के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय पर गंभीर अन्याय किया गया है। लोग आपसे सेकुलरिज्म के साथ खड़े रहने को कहते हैं।' असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'क्या यह सच नहीं है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब इसी बंगाल से लगभग 40,000 मुसलमानों को नोटिस दिए गए या उन्हें यहां से निर्वासित कर दिया गया था?' ओवैसी ने बीड़ी रोलने वाली महिलाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी नीति लागू करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा, 'बीड़ी रोलकर अपनी आजीविका चलाने वाली हमारी माताओं और बहनों के लिए न्यूनतम मजदूरी नीति लागू की जाएगी।' एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए थे। उनमें से 3,50,000 प्रमाणपत्र मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के थे। पश्चिम बंगाल में जो भी विकास हो रहा है, वह सिर्फ कोलकाता की ओर केंद्रित है।

अंबेडकर जयंती: सीएम योगी, केशव प्रसाद, ब्रजेश पाठक, पंकज चौधरी ने किया बाबासाहेब को नमन

लखनऊ , एजेंसी। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित दी। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब के संवैधानिक आदर्श ही देश को समानता, न्याय और सशक्त समाज की दिशा देते हैं।

सभी नेताओं ने उनके बताए मार्ग पर चलकर समतामूलक और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि समता, न्याय और बंधुत्व के उच्च आदर्शों से आलोकित, समरस एवं समावेशी समाज की आधारशिला रखने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार 'भारत रत्न' बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। अंत्योदय और लोक-कल्याण के प्रति समर्पित बाबा साहब सच्चे अर्थों में माँ भारती के अमूल्य रत्न हैं। उनका प्रेरक जीवन हम सभी के लिए सदैव पथप्रदर्शक रहेगा।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लिखा कि भारतीय संविधान के शिल्पी, महान समाज सुधारक, 'भारत रत्न' बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जी की जयंती पर सादर नमन। वंचितों एवं उपेक्षितों के अधिकारों की आवाज बनकर बाबा साहेब ने समाज में समानता, न्याय और बंधुत्व की मजबूत नींव रखी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सामाजिक न्याय के

अग्रदूत, संविधान शिल्पी 'भारत रत्न' बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा को परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाकर वंचितों, श्रमिकों और किसानों को अधिकार दिलाते हुए समता, न्याय और मानव गरिमा की अटूट आधारशिला रखी। उनका संघर्षमय जीवन आज भी कर्तव्य, समर्पण और राष्ट्रसेवा का मार्ग आलोकित करता है।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर लंबे चक्कर का झंझट खत्म, बिजवासन टोल पर यूटर्न अंडरपास दिलाएगा ट्रैफिक जाम से मुक्ति

नया गुरुग्राम, एजेंसी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बढ़ती यातायात समस्याओं और दुर्घटना जोखिम को देखते हुए बिजवासन टोल प्लाजा के पास यू-टर्न अंडरपास निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया है जिसमें करीब साढ़े आठ एकड़ जमीन की आवश्यकता बताई गई है। जमीन उपलब्ध होते ही प्रोजेक्ट का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा। दरअसल टोल प्लाजा के आसपास यूटर्न की सुविधा नहीं होने से वाहन चालकों को लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। कई बार चालक टोल से बचने या रास्ता छोटा करने के लिए गलत दिशा में वाहन मोड़ देते हैं, जिससे हादसों की आशंका बढ़ जाती है। स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए की ओर से लंबे समय से इस समस्या के समाधान की मांग की जा रही थी।

28 जनवरी को एनएचएआई अध्यक्ष संतोष यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक में जीएमडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी यू-टर्न के अभाव से हो रही दिक्कतों को रखा। इसके बाद एनएचएआई ने सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार दो लेन के यू-टर्न अंडरपास के लिए करीब पौने सात एकड़ जमीन जीएमडीए की और लगभग पौने दो एकड़ जमीन निजी बिल्डरों की लगेगी। सरकारी जमीन को जीएमडीए के माध्यम से उपलब्ध कराने और निजी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाने की योजना है। सलाहकार कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यू-टर्न न होने से यात्रियों का समय और ईंधन दोनों अधिक खर्च हो रहे हैं। टोल प्लाजा के आसपास ट्रैफिक दबाव बढ़ रहा है और अचानक लेन बदलने या गलत दिशा में चलने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इस सुविधा के अभाव का असर सेक्टर-106 से 115 तक के इलाकों के अलावा साईं कुंज, बजघेड़ा, पालम विहार, न्यू पालम विहार, चंदन विहार, उपवन सोसायटी, साहिब कुंज, निहाल कालोनी, चौमा और आसपास की कॉलोनियों पर पड़ रहा है।

कुंभ की 'वायरल गर्ल' मोनालिसा के पति को हाईकोर्ट से राहत

खुलकर समर्थन में उतरे वामपंथी नेता

कोच्चि, एजेंसी। केरल हाईकोर्ट ने 'कुंभ मेला फेम' मोनालिसा भोसले के पति मोहम्मद फरमान खान को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की है। यह राहत उस अपहरण के मामले में दी गई है, जो कथित तौर पर मोनालिसा के पिता द्वारा मध्य प्रदेश में दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मोनालिसा नाबालिग हैं और फरमान ने उनका अपहरण किया है। इस बीच वामपंथी नेताओं ने खुलकर मोनालिसा का समर्थन किया है साथ ही भाजपा पर भी निशाना साधा है। आइए पूरा मामला समझते हैं।

पिछले महीने केरल हाईकोर्ट में दायर अपनी संयुक्त याचिका में, इस जोड़े ने स्पष्ट किया कि मोनालिसा इस साल (2026) जनवरी में 18 साल की हो गई थी। उसका कहना है कि मार्च में जब उसने फरमान से शादी की, तब वह पूरी तरह से बालिग थी। इसी आधार पर, जोड़े ने अपनी शादी को लेकर दर्ज हो सकने वाले किसी भी मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। उन्हें इस बात का डर था कि मध्य प्रदेश में दर्ज कथित अपहरण के मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने

23 मार्च को याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि दोनों ने शादी की है और अब वे पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- दस्तावेज से पता चलता है कि आवेदकों ने 11 मार्च 2026 को शादी की है। इन परिस्थितियों को देखते हुए, अगली सुनवाई तक आवेदकों को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया जाता है।

8 अप्रैल को हुई सुनवाई में अदालत ने गिरफ्तारी से मिली इस सुरक्षा को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। 20 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अदालत ने यह कदम वरिष्ठ लोक अभियोजक के उस बयान के बाद उठाया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई जवाब या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

केरल विवाह पंजीकरण (सामान्य) नियम, 2008 के तहत जारी उनका विवाह प्रमाण पत्र। मोनालिसा के 18 वर्ष का होने का प्रमाण देने के लिए उनका जन्म प्रमाण पत्र मोनालिसा का आधार कार्ड।

याचिका में एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि मोनालिसा के परिवार ने शुरुआत में इस शादी के लिए अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन बाद में परिवार के ही एक रिश्तेदार के प्रभाव में आकर उन्होंने इस शादी का विरोध करना शुरू कर दिया।

मोनालिसा भोसले कौन है और कैसे शुरू हुआ विवाद?

मोनालिसा भोसले पिछले साल (2025) कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई थी। मेले में मनके बेचते हुए उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसके बाद अपनी सादगी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वह रातों-रात मशहूर हो गई थी। इस जोड़े के अनुसार, उनकी मुलाकात एक मलयालम फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और 11 मार्च को उन्होंने केरल में शादी कर ली। मीडिया में इस शादी की काफी चर्चा हुई थी। उनके इस अंतर-धार्मिक विवाह ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कुछ वर्गों और मोनालिसा के पिता ने दावा किया कि मोनालिसा की उम्र अभी केवल 16 वर्ष है और इसलिए वह कानूनी तौर पर शादी करने के योग्य नहीं हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी कथित तौर पर जांच शुरू कर दी है। इस बात को लेकर चिंताएं जताई जा रही थीं कि क्या यह शादी अवैध है और क्या इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं। गिरफ्तारी की आशंका के बीच केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले इस जोड़े ने अपनी उम्र और शादी को वैध साबित करने के लिए कई अहम दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखे हैं।